



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112020-223376
CG-DL-E-27112020-223376

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 342]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 27, 2020/आग्रहायण 6, 1942

No. 342]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 27, 2020/AGRAHAYANA 6, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2020

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. ओआई- 22/2019

विषय: थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बसों और लारियों के लिए ट्यूब और/अथवा फलैप के साथ अथवा उसके बिना रबड़ के नए किस्म के “न्यू न्यूमेटिक रेडियल टायर्स” के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा.सं. 6/30/2019-डीजीटीआर.—क. पृष्ठभूमि:

ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) (जिसे इसके बाद “आवेदक” भी कहा गया है) ने घरेलू उद्योग जिसमें अपोलो टायर्स लिमिटेड, जे.के. टायर इंडस्ट्रीज लि., सीएट लि. और एमआरएफ लि. (जिसे इसके बाद “याचिकाकर्ता/आवेदक कंपनियां” भी कहा गया है) शामिल थे जो एटीएमए के सदस्य हैं, की ओर से पाटनरोधी जांच आरंभ करने के लिए और थाईलैंड (जिसे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बसों और लारियों के

लिए ट्यूब और/अथवा फ्लैप (जिसे “संबद्ध वस्तु” भी कहा गया है) के साथ अथवा उसके बिना रबड़ के नए “न्यू न्यूमेटिक रेडियल टायर्स” के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए एक आवेदन दायर किया।

2. जबकि प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन के मौजूद रहने, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तथा सीमा शुल्क की राशि जिसे अगर लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, की सिफारिश करने के लिए इस नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 2 दिसंबर, 2019 की अधिसूचना सं. 6/30/2019-डीजीटीआर के संदर्भ में एक आम नोटिस जारी किया।

ख. प्रक्रिया

3. प्राधिकारी द्वारा इस संबद्ध जांच के संबंध में इसमें नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

- i. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार इन जांचों को आरंभ करने की कार्यवाही करने के पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 2 दिसंबर, 2019 की अधिसूचना 6/30/2019-डीजीटीआर जारी की।
- iii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों का आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पते के अनुसार जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे इस जांच की शुरुआत के संबंध में सूचना देते हुए प्राधिकारी द्वारा पत्र के जारी किए जाने की तिथि से 37 दिनों के भीतर अथवा विस्तारित समय-सीमा में लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत कराएं।
- iv. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास और ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को इस आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध कराई।
- v. प्राधिकारी ने थाईलैंड में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों जिनका विवरण आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया था, को संगत सूचना प्राप्त करने के लिए निर्यातक की प्रभावली भेजी और उन्हें इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत कराने के लिए अवसर दिया:

- क) कॉन्टीनेंटल टायर्स कं., लि. थाईलैंड
- ख) डीस्टोन लि. थाईलैंड
- ग) गुडईयर (थाईलैंड) पब्लिक कं. लि.
- घ) हिहेरो कंपनी लिमिटेड
- ड) हुआयी ग्रुप कं. लि. थाईलैंड
- च) लिंगलॉग इंटरनेशनल टायर
- छ) मैक्सिस इंटरनेशनल
- ज) माईकलिन सियाम कं. लि.

- झ) ओटानी रेडियल कं. लि.
- ञ.) सेंचुरी टायर (थाईलैंड) कं. लि.
- ट) सियाम रबड़ लि.
- ठ) एसआर टायर्स कं. लि.
- ड) सुमिटोमो कारपोरेशन थाईलैंड लि.
- ढ) वी रबड़ कारपो. लि.
- ण) योकोहामा टायर सेल्स (थाईलैंड) कं. लि.
- त) झोंगसी रबड़ ग्रुप

vi. उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

- क) मै. ब्रिजस्टोन एशिया पैसिफिक प्रा. लि. (बीएससीएपी)
- ख) मै. ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाईलैंड) कं. लिमिटेड (बीटीएमटी) तथा मै. थाई ब्रिजस्टोन कं. लि. (कंबाईंड)
- ग) मै. एलएलआईटी (थाईलैंड)
- घ) मै. झोंगसी रबड़ (थाईलैंड) कं. लि.
- ड) मै. डीस्टोन कारपोरेशन लिमिटेड
- च) मै. माइकेलिन सियाम कं., लि.
- छ) मै. सियाम ट्रक रेडियल कंपनी लिमिटेड

vii. मैक्सिस इंटरनेशनल (थाईलैंड) कं. लि. द्वारा केवल लिखित अनुरोध दायर किया गया है। मै. ओतानी रेडियल कं. लि. ने प्राधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र की प्राप्ति की पावती भेजी है।

viii. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी:

- 1) ए.जी. इंडस्ट्रीज, हरियाणा
- 2) ए.एस. एंड कंपनी, दिल्ली
- 3) आदित्य सेल्स कारपोरेशन, दिल्ली
- 4) एजीके डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली
- 5) अखिल इम्पैक्स बिल्डिंग, पंजाब
- 6) एलायंस ट्रेडर्स, दिल्ली
- 7) अमित इंटरप्राइजेज, पंजाब
- 8) अरोरा इंटरप्राइजेज, उत्तर प्रदेश

- 9) असिस इंटरप्राइजेज, महाराष्ट्र
- 10) भगवती इम्पेक्स, दिल्ली
- 11) कैपटाउन ओवरसीज, दिल्ली
- 12) सेलाइट टायर कारपोरेशन, गुजरात
- 13) चड्ढा टायर ट्रेडर्स, दिल्ली
- 14) छाबड़ा सेल्स कारपोरेशन, दिल्ली
- 15) दशमेश ट्रेडिंग कं., महाराष्ट्र
- 16) दीप इंटरप्राइजेज, उत्तर प्रदेश
- 17) दिल्ली टायर शॉप, दिल्ली
- 18) अकनूर टायर्स प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र
- 19) इलैक्ट्रो लिंक, केरल
- 20) ऐसइन्फ्राप्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र
- 21) फाइन ट्रेडर्स, दिल्ली
- 22) फिश एक्वारियम होम, दिल्ली
- 23) गनपति ओवरसीज, दिल्ली
- 24) जेनेटिक सेल्स कारपोरेशन, दिल्ली
- 25) ग्लोब्स कारपोरेशन, महाराष्ट्र
- 26) गुप्ता टायर हाउस, हरियाणा
- 27) एचडी इंटरनेशनल, पंजाब
- 28) एच एस अरोड़ा ऐंड कं., दिल्ली
- 29) एच एस इंटरनेशनल, दिल्ली
- 30) हरप्रीत इंटरनेशनल, दिल्ली
- 31) हेयेर ट्रेडिंग कं., महाराष्ट्र
- 32) हिंद ट्रेडर्स, महाराष्ट्र
- 33) हिंद ट्रेडर्स, दिल्ली
- 34) इंडियन रबड़ मैनुफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, महाराष्ट्र
- 35) इंडो चाइना इम्पेक्स, दिल्ली
- 36) इंडो सिलिकॉन इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि., दिल्ली

- 37) इंटरनेशनल बिजनेस ग्रुप, महाराष्ट्र
- 38) जे एम शमा डिजाइन्स, महाराष्ट्र
- 39) जैपेक्स महाराष्ट्र
- 40) जितेन्द्र ओवरसीज, दिल्ली
- 41) जुनेजा एजेंसीज, पंजाब
- 42) के.सी.इम्पैक्स, दिल्ली
- 43) कबीर कम्पोनेंट्स प्रा. लि., दिल्ली
- 44) काक्स ऐंड बिल्स प्रा. लि., दिल्ली
- 45) किंग्सटन इंटरप्राइजेज, दिल्ली
- 46) लोकेश इम्पैक्स, राजस्थान
- 47) एम एस इंटरनेशनल, दिल्ली
- 48) मानकेश ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली
- 49) मीनाक्षी इम्पोर्टर्स, महाराष्ट्र
- 50) मोहन इंटरप्राइजेज, दिल्ली
- 51) नन्द रबड़ प्रा. लि., हरियाणा
- 52) नेशनल ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली
- 53) न्यू विकास टायर्स, दिल्ली
- 54) पाहवा डिस्ट्रीब्यूटर्स, उत्तर प्रदेश
- 55) पारस ऑटो पार्ट्स, गुजरात
- 56) प्रदीप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, महाराष्ट्र
- 57) पायनीर ट्रेडिंग कारपोरेशन, महाराष्ट्र
- 58) प्रिकॉन इंजीनियरिंग सर्विसेज, महाराष्ट्र
- 59) प्रेम ट्रेडिंग कंपनी, मध्य प्रदेश
- 60) प्रिकॉन इंजीनियरिंग सर्विसेज, दिल्ली
- 61) आर सी इंटरनेशनल, महाराष्ट्र
- 62) आर एस इंटरप्राइजेज, महाराष्ट्र
- 63) राधेकिशन इंटरप्राइजेज, दिल्ली
- 64) रायपाल रोडलाइन्स प्रा. लि., महाराष्ट्र
- 65) रामेश्वर दास ऐंड कं., हरियाणा

- 66) रांगी रोड कैरियर, महाराष्ट्र
- 67) रेनु राज ट्रेडिंग, महाराष्ट्र
- 68) रोडलायन इंटरनेशनल, दिल्ली
- 69) रॉयल ट्रेडर्स, दिल्ली
- 70) राइना ओवरसीज (इंडिया), महाराष्ट्र
- 71) एस आर इंटरप्राइजेज, दिल्ली
- 72) एस.एस. एंड संस, दिल्ली
- 73) एस.के. इंटरनेशनल, दिल्ली
- 74) सारवन इंटरप्राइजेज, दिल्ली
- 75) सभरवाल ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली
- 76) सचिव प्रसाद यादव, वेस्ट बंगाल
- 77) समर ट्रेडर्स, दिल्ली
- 78) संजोगइंपेक्स, मध्य प्रदेश
- 79) सनमतिपोरटेक्स प्रा. लि., दिल्ली
- 80) सत गुरु ट्रेडर्स, उत्तर प्रदेश
- 81) सवीर इंटरनेशनल, दिल्ली
- 82) शिव शक्ति इंटरप्राइजेज, दिल्ली
- 83) शिवालिक एक्जिम, पंजाब
- 84) सिमरन इंडिया इन्क., दिल्ली
- 85) सिमरन ट्रेडर्स, दिल्ली
- 86) सोम प्रोजेक्ट्स एंड एसोसिएट्स, दिल्ली
- 87) श्री एंड कं., कर्नाटक
- 88) श्री कुमारन ट्रेडर्स, कर्नाटक
- 89) श्री टायर्स, कर्नाटक
- 90) सुमंतबल्लावल, वेस्ट बंगाल
- 91) सन ट्रेडर्स, दिल्ली
- 92) सुप्रीम ट्रेडिंग कारपोरेशन, दिल्ली
- 93) सूर्योदय सेल्स, दिल्ली

- 94) ट्रांस टायर्स (इंडिया) प्रा.लि., महाराष्ट्र
- 95) यूनिग्लोरी इंटरनेशनल, दिल्ली
- 96) वान सेल्स इंडिया प्राइवेट लि., दिल्ली
- 97) विकास रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली
- 98) बोरटेक्स रबड़ इंडस्ट्रीज प्रा. लि., दिल्ली
- 99) वृंदा ओवरसीज, दिल्ली
- 100) जाफको इंडिया प्रा. लि., दिल्ली

- ix. उपर्युक्त के उत्तर में, निम्नलिखित आयातों/प्रयोक्ताओं ने उत्तर प्रस्तुत किया है और/अथवा अनुरोध किया है:
- i. ब्रिजस्टोन इंडिया प्रा. लि.
 - ii. जाफको इंडिया प्रा. लि.
 - iii. फोर्स मोटर्स लि.
 - iv. रेनाल्ट इंडिया प्रा. लि.
 - v. ट्रिम्प मोटरसाइकिल (इंडिया) प्रा. लि.
- x. प्राधिकारी ने अनुरोध किए जाने पर निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर (इक्यूआर) प्रस्तुत करने के लिए 24.01.2020 तक समय विस्तार मंजूर किया जिसे की वेब-साइट के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था।
- xi. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उसमें किए गए अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेब-साइट पर अपलोड की गई थी ताकि उनके अनुरोधों के अगोपनीय पाठ सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल किया जा सके क्योंकि सार्वजनिक फाइल वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण भौतिक रूप से प्राप्त किए जाने लायक नहीं थी।
- xii. प्राधिकारी ने भारत में घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और क्षति रहित कीमत को तय करने के लिए अनुबंध-III में निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर संभव सीमा तक की है जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन की तुलना में कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xiii. आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से उस सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन उस सीमा तक किया गया था , जिस सीमा तक उसे वर्तमान जांच के उद्देश्य से आवश्यक माना गया।
- xiv. वर्तमान पाटनरोधी जांच के प्रयोजन से जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2018 से 30 जून, 2019 तक (15 माह) है। हालांकि क्षति की जांच की अवधि को अप्रैल 2015-मार्च, 2016, अप्रैल 2016-मार्च, 2017, अप्रैल 2017 – मार्च 2018, और जांच की अवधि के रूप में माना गया है। चूंकि जांच की यह अवधि 15 महीने की एक अवधि है अतः उसे क्षति के आकलन के उद्देश्य से पूर्व के वर्षों की तुलना किए जाने के लिए “वार्षिकीकृत” किया गया है।

- xv. पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन-देनवार ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंड) से अनुरोध किया गया था और प्राधिकारी द्वारा उसे प्राप्त कर लिया गया है। प्राधिकारी ने लेन-देन की उचित जांच के पश्चात आयातों की मात्रा की गणना और इसके विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- xvi. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर उस सीमा तक इन अंतिम जांच-परिणामों में प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से विचार किया गया है जिस सीमा तक उसके समर्थन में साक्ष्य दिया गया है और उसे वर्तमान जांच के लिए संगत माना गया है।
- xvii. इस नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 21 अक्तूबर, 2020 को हुई मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया जिसमें विभिन्न पक्षकारों द्वारा भाग लिया गया था। मौखिक सुनवाई कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम की गई थी। सभी पक्षकारों, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए थे, से अनुरोध किया गया था कि वे अपने दृष्टिकोण को लिखित अनुरोध के रूप में प्रस्तुत करें जिससे कि हितबद्ध पक्षकार उसके बाद प्रति-उत्तर प्रस्तुत करने में सक्षम हो सके।
- xviii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी, संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों का प्रकट नहीं की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराएं।
- xix. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच दिए जाने से इंकार किया है, अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराया है या इस जांच में काफी हद तक बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान जांच परिणाम जारी किया।
- xx. इस नियमावली के नियम 16 के अनुसार, इस जांच के आवश्यक तथ्यों को दिनांक 13 नवंबर, 2020 के प्रकटन विवरण के संदर्भ में ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था और उत्तर में प्राप्त टिप्पणियों जिसे प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया, का समाधान इन अंतिम जांच परिणामों में किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश प्रकटन पश्चात अनुरोध पूर्व में उनके द्वारा किए गए अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र है। हालांकि जिस सीमा तक संगत माना गया है, उस सीमा तक प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच इन अंतिम जांच परिणामों में की जा रही है।
- xxi. इन अंतिम जांच परिणामों में *** गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा वैसी मानी गई सूचना का द्योतक है।
- xxii. () में दी गई सूचना नकारात्मक संख्या/रेंज को दर्शाती है।
- xxiii. इस जांच की अवधि के दौरान यूएसडालर1=70.73 की प्रचलित औसत विनिमय दर प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच के लिए ली गई है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

“2 वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद को 40112010 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य “बसों और लारियों के लिए ट्यूब और/अथवा फ्लैप के साथ अथवा उसके बिना रबड़ का न्यू न्यूमेटिक रेडियल टायर्स” है।

3. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयात की गई संबद्ध वस्तुओं में मानदंडों जैसे भौतिक और तकनीकी विशेषताएं, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, इन वस्तुओं का कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और शुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय विशेषताएं हैं और ये दोनों तकनीकी रूप से तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इस कारण से इन्हें इस नियमावली के अंतर्गत "समान वस्तु" के रूप में माना जाना चाहिए। प्रथम दृष्टया जांच के आधार पर यह नोट किया जाता है कि भारत में याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात किए जा रहे संबद्ध वस्तुओं का "समान वस्तु" के रूप में माना जाता है।"

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

5. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में किया गया अनुरोध नीचे दिया गया है:

- i. विचाराधीन उत्पाद को 40112010 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य बसों और लारियों में एक प्रकार का उपयोग किए जाने वाली ट्यूब और/अथवा फ्लैप के साथ अथवा उसके बिना रबड़ का "न्यू न्यूमेटिक रेडियल टायर्स" है।
- ii. टायर दो प्रकार का हो सकता है, ट्यूब प्रकार अथवा ट्यूबलेस (बिना ट्यूब और फ्लैप के)। ट्यूब प्रकार के उत्पाद में, टायर का उपयोग किसी वाहन में एक ट्यूब और एक फ्लैप के साथ किया जाता है। एक टायर, एक ट्यूब और एक फ्लैप की बिक्री एक साथ "टायर सेट" के रूप में की जाती है। पारिभाषिक शब्द "टीटीएफ" उद्योग में प्रचलित है जो "टायर सेट" को दर्शाता है। टायर, ट्यूब और फ्लैप किसी वाहन में संयुक्त रूप से "टायर" का कार्य करते हैं। टायरों के भीतर ट्यूब में हवा भरी जाती है और फ्लैप का उपयोग पहिये और ट्यूब के बीच किया जाता है ताकि ट्यूब के फट जाने से बचा जा सके। टायर, ट्यूब और फ्लैप का उत्पादन इन उत्पादकों द्वारा पृथक् रूप से किया जाता है। टायर, ट्यूब और फ्लैप की बिक्री प्राथमिक रूप से "टीटीएफ" अथवा "टायर सेट" आधार पर होती है।
- iii. बसों और लारियों/ट्रकों में उपयोग किए जाने वाले रेडियल टायर, ट्यूब और फ्लैप को इस तथ्य पर विचार किए बिना विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया गया है कि क्या वे टीटीएफ रूप में या अलग-अलग टायर, ट्यूब और फ्लैप के रूप में हैं। ट्यूब रहित रेडियल टायर जहां ट्यूब और फ्लैप अपेक्षित नहीं हैं, भी इस जांच के दायरे में हैं। टायर, ट्यूब और फ्लैप का उत्पादन पृथक् रूप से किया जाता है। हालांकि, उनका उपयोग अनिवार्य तौर पर ऑटोमोटिव उपयोगों में एक साथ किया जाता है।
- iv. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमा शुल्क उप शीर्षक सं. 4011.20 के अंतर्गत अध्याय 40 में किया जाता है और ट्यूब और फ्लैप का वर्गीकरण क्रमशः 4013.1010/4013.1020 और 4012.9049 के अंतर्गत किया जाता है। हालांकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार की जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
- v. आवेदक कंपनियों द्वारा उत्पादन किए गए उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यात की गई संबद्ध वस्तु में कोई अंतर नहीं है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

6. संबद्ध जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।
- (क) डिस्टोन कारपोरेशन लिमिटेड और सियाम ट्रक रेडियल कंपनी लिमिटेड ने पहले पीसीएन प्रणाली का प्रस्ताव किया। प्रस्तावित पीसीएन संरचना यह तर्क देते हुए टायरों/भीतरी आयाम/ट्यूब की किस्म/फ्लैप की चौड़ाई/प्रकार के आधार पर थी, कि यह प्रत्येक घटक बिक्री कीमत एवं लागत को प्रभावित करते हैं।

- (ख) ब्रिजस्टोन ने आरंभिक तौर पर (i) टायर (ii) टायर + ट्यूब (iii) टायर + ट्यूब + फ्लैप (iv) टायर + फ्लैप पर विचार करते हुए पीसीएन का प्रस्ताव किया। ब्रिजस्टोन ने यह तर्क दिया कि पीसीएन तकनीकी विशेषताओं (अर्थात् निष्पादन भौतिक विशेषताओं, कीमत, लागत और प्रयोग अंतर) में अंतर के आधार पर नहीं थे, परंतु भिन्न उत्पाद संयोजन (फ्लैप और/अथवा ट्यूब सहित या उसके बिना) द्वारा निर्धारित थे। ब्रिजस्टोन ने यह अनुरोध किया कि विभिन्न पीसीएन के तहत समान टायर के संबंध में उत्पादन लागतों में कोई अंतर नहीं है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद(पीयूसी) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के टैरिफ शीर्षक 40112010 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य “बसों और लॉरियों के लिए ट्यूब और/अथवा फ्लैप के साथ अथवा उसके बिना रबड़ का न्यू न्यूमेटिक रेडियल टायर्स” है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में ट्यूब प्रकार और ट्यूब रहित प्रकार दोनों रेडियल टायर शामिल हैं।
8. ट्यूब प्रकार के टायर में, टायर का उपयोग किसी वाहन में एक ट्यूब और एक फ्लैप के साथ किया जाता है। एक टायर, एक ट्यूब और एक फ्लैप की बिक्री एक साथ “टायर सेट” के रूप में की जाती है और उसका उल्लेख “टीटीएफ” के रूप में किया जाता है। पारिभाषिक शब्द “टीटीएफ” उद्योग में प्रचलित है जो “टायर सेट” को दर्शाता है। टायर, ट्यूब और फ्लैप किसी वाहन में संयुक्त रूप से “टायर” का कार्य करते हैं। टायर दो प्रकार का हो सकता है, ट्यूब प्रकार अथवा ट्यूबलेस (बिना ट्यूब और फ्लैप के)। ट्यूब प्रकार के उत्पाद में, टायर का उपयोग किसी वाहन में एक ट्यूब और एक फ्लैप के साथ किया जाता है। एक टायर, एक ट्यूब और एक फ्लैप की बिक्री एक साथ “टायर सेट” के रूप में किया जाता है। पारिभाषिक शब्द “टीटीएफ” उद्योग में प्रचलित है जो “टायर सेट” को दर्शाता है। टायर, ट्यूब और फ्लैप की बिक्री प्राथमिक रूप से “टीटीएफ” अथवा “टायर सेट” आधार पर होती है। ट्यूब रहित रेडियल टायर जहां ट्यूब और फ्लैप की आवश्यकता नहीं होती है, भी इस जांच के दायरे में आता है।
9. आयात किए गए उत्पाद के दायरे में बसों और लॉरियों/ट्रकों में उपयोग किए जाने वाले केवल रेडियल टायर शामिल हैं। सामान्य तौर पर टायरों का उपयोग विभिन्न प्रकारों के वाहनों जैसे ट्रकों, बसों, लॉरियों, हल्के वाणिज्यिक वाहनों, पैसेंजर कार, जीप, ट्रैक्टर, ट्रू-व्हीलर, थ्री व्हीलर, पशु द्वारा खींचे जाने वाले वाहनों, अर्थमूवर्स, औद्योगिक टॉयर्स, एयर क्राफ्ट्स आदि में किया जाता है। हालांकि, विचाराधीन उत्पाद वह प्रकार है जिसका उपयोग पशु और लॉरियों/ट्रकों में किया जाता है। सभी अन्य प्रकार के टायर वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।
10. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 40 के अंतर्गत किया जाता है। रेडियल टॉयर्स का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ मद 40112010 के अंतर्गत किया जाता है जबकि ट्यूब और फ्लैप का वर्गीकरण क्रमशः 40131020 और 40129049 के अंतर्गत किया जाता है। नए/उपयोग न किए गए न्यूमेटिक रेडियल टायरों के बिना आयात किए गए ट्यूबों और/अथवा फ्लैप विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
11. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह मानते हैं कि भारतीय घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तुओं पर थाईलैंड से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदकों द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तुओं और थाईलैंड से आयात की गई संबद्ध वस्तु उत्पाद विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, इन वस्तुओं का कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा शुल्क वर्गीकरण के मामले में तुलनीय हैं। आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।
12. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि वर्तमान जांच में पीसीएन किया जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि जिन हितबद्ध पक्षकारों ने पीसीएन सिद्धांत का प्रयोग करने की मांग की थी, उन्होंने अपना सुझाव वापस ले लिया। इसके अतिरिक्त, किसी भी पक्षकार ने संगत सूचना या पर्याप्त तर्क पीसीएन सिद्धांत के प्रयोग का औचित्य देते हुए प्रदान नहीं किया है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध सामान विगत में पाटनरोधी और सब्सिडीरोधी जांच के

अध्यधीन रहे हैं, जिनमें प्राधिकारी ने पीसीएन सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया है। अतः प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए पीसीएन सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया है।

घ. घरेलू उद्योग का कार्य-क्षेत्र एवं स्थिति

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

13. घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र की स्थिति के बारे में जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध नीचे दिया गया है:

- i. यह आवेदन सभी संबंधित सूचना/आंकड़े उपलब्ध कराकर वर्तमान आवेदन में भाग लेने वाले एटीएमए की चार सदस्य कंपनियों अर्थात् मै. ओपोलो टायर्स लि., मै. सीएट लि., मै. जे.के. टायर इंडस्ट्रीज लि. और एमआरएफ लि. के साथ ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ("एटीएमए" अथवा आवेदक/आवेदक एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया है क्योंकि वे भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक हैं। आवेदकों को छोड़कर संबद्ध वस्तुओं के पांच अन्य उत्पादक हैं अर्थात् मै. बिरला टायर, मै. गुडईयर इंडिया लि., मै. ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मै. मिकेलिन इंडिया प्रा. लि., और मै. कॉन्टीनेंटल इंडिया लि.।
- ii. आवेदक कंपनियों ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देश के किसी निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से भी संबंधित नहीं हैं।
- iii. आवेदक कंपनियों के पास विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है और वे भारत में संबद्ध वस्तुओं का 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करते हैं। तदनुसार, आवेदक कंपनियां "घरेलू उद्योग" हैं और वे पाटनरोधी नियमावली नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) के संदर्भ में स्थिति की आवश्यकता को पूरा करते हैं।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

14. किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

16. यह आवेदन घरेलू उत्पादकों नामतः अपोलो टायर्स लि., जे.के. टायर इंडस्ट्रीज लि., एमआरएफ लि. और सीएट लि. की ओर से ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया है। आवेदक कंपनियों ने वर्तमान जांच के लिए संगत सूचना उपलब्ध कराई है।
17. रिकॉर्ड पर सूचना दर्शाती है कि आवेदक कंपनियों ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का न तो आयात किया है और न ही वे भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातकों अथवा थाईलैंड से संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातकों से संबंधित हैं।
18. आवेदक कंपनियों का उत्पादन भारतीय उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक है और इस प्रकार यह कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है।

19. इस प्रकार प्राधिकारी मानते हैं कि याचिकाकर्ता कंपनियों का भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है और इस जांच के उद्देश्य से वे नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति की आवश्यकता को पूरा करते हैं और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के संदर्भ में घरेलू उद्योग हैं।

ड. गोपनीय और विविध अनुरोध

ड..1 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

20. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के मुद्दे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. आवेदक कंपनियों ने दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार नोटिस सं. 10/2018 के अनुसार तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार इस आवेदन के अगोपनीय पाठ में सभी आवश्यक सूचना प्रकट की हैं।
- ii. गोपनीयता संबंधी दावे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना तक सीमित हैं। सूचीबद्ध सूचना जहां भी संभव हुआ है, दी गई है और जांच विवरण का संशोधित अगोपनीय रूपांतर दिया गया है।
- iii. निर्यातकों ने खुद ही आवेदकों को प्रभावी रूप से टिप्पणियां प्रदान करने से रोकते हुए गोपनीयता मानदंडों का उल्लंघन किया है।
- iv. आवेदकों ने आयातों, आयात कीमत, पाटन मार्जिन और पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक होने वाले कई आर्थिक मानदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में पर्याप्त सूचना प्रदान की है। हितबद्ध पक्षकार प्राधिकारी द्वारा जांच की शुरुआत से पूर्व काफी समय दिए जाने पर पर्याप्तता के संबंध में टिप्पणियां देने में विफल रहे।
- v. चीनी उद्यमों पर वैश्विक रूप से पाटनरोधी अथवा प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने से ये उत्पादक चीन से बाहर के देशों में निवेश कर रहे हैं। सब्सिडीशुदा कच्ची सामग्री की उपलब्धता के कारण थाइलैंड में काफी निवेश हुए हैं। इससे थाइलैंड से भारत सहित कई देशों को टायरों का काफी निर्यात हुआ है।
- vi. पूर्व में व्यापार उपचार चीन से होने वाले पाटित आयातों को हल करने के लिए थे और नए स्रोत अर्थात् थाइलैंड से पाटित आयातों का कोई संबंध नहीं था। टायर को प्रतिबंधित श्रेणी में ले जाने से केवल लाइसेंस की आवश्यकता जुड़ जाती है और टायरों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इससे आयातों की मात्रा और कीमत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- vii. आवेदकों ने निर्यात कीमत परिकलन और किए गए समायोजनों पर अनुबंध जोड़ते हुए गलती से चूक की है। ऐसा प्रतीत होता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने इस सूचना को बहुत कम महत्व दिया है, अन्यथा इसका अनुरोध काफी पूर्व के स्तर पर किया जा सकता था। किसी भी दशा में याचिका में सीआईएफ कीमतों और कारखानागत कीमतों के संबंध में सूचना है। संशोधित अनुबंध प्रपत्र ज के लिए दिए गए हैं।
- viii. IVक और अनुबंध-1.3 में दिए गए आंकड़ों के बीच कोई विसंगति नहीं है। दोनों अनुबंधों में आंकड़ों का स्रोत डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित आंकड़े हैं। तथापि, अनुबंध-4.1 में दी गई सूचना थर्ड सीमा शुल्क आंकड़ों से ली गई है।
- ix. प्राधिकारी ने चीन से संबंधित जांचों के लिए प्रतिस्थापन बाजार और ओईएम बाजार के लिए अलग-अलग विश्लेषण नहीं किया है।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

21. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. आवेदक कंपनियों ने प्राधिकारी द्वारा जारी की गई व्यापार सूचना 10/2018 में दिए गए अनुदेशों का पालन नहीं किया है। उसके विपरीत आवेदक कंपनियों ने अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक मानदंडों को गोपनीय रखा है। इस प्रकार की सूचना के प्रकटन के बिना, प्रतिवादी आवेदक कंपनियों के क्षति संबंधी मानदंडों की सार्थक जांच करने के लिए सक्षम नहीं हो पाएगी। आवेदक कंपनियों द्वारा दावा की गई गोपनीयता अत्यधिक है।

- ii. आवेदक ने यह दावा करते हुए कि वास्तविक आंकड़े उनकी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को प्रतिस्पर्धी लाभ दे सकते हैं, एक अनुक्रमित रूप में भाग लेने वाली कंपनियों के आर्थिक मानदंडों के लिए अधिकांश आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। हालांकि यदि भाग लेने वाली कंपनियों का समग्र आंकड़ा वास्तविक आधार पर दिया जाता है तब भाग लेने वाली कंपनियों का अलग-अलग आंकड़ा समझने लायक नहीं होगा। प्रतिवादी अथवा किसी अन्य प्रतिस्पर्धी को कोई प्रतियोगी लाभ नहीं मिलेगा।
- iii. इन मानदंडों जैसे क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सा आदि के संबंध में सूचना चीन जन.गण. के विरुद्ध पाटनरोधी जांच में जारी किए गए अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा प्रकट की गई है। चार में से तीन भाग लेने वाली कंपनियां वर्तमान जांच के लिए सामान्य हैं और चीन टीबीआर पर पाटनरोधी जांच के लिए सामान्य है। एमआरएफ लिमिटेड, जो पूर्व में की गई पाटनरोधी जांच का हिस्सा नहीं था, ने विशेष रूप से इस याचिका का समर्थन किया। उस मामले में, इन आंकड़ों को गोपनीय के रूप में नहीं माना गया था परंतु अब इसे गोपनीय के रूप में दावा किया जा रहा है।
- iv. आवेदक ने निवल निर्धारित परिसंपत्तियों, कार्यशील पूंजी और नियोजित पूंजी के संबंध में पूर्ण और अत्यधिक गोपनीयता का भी दावा किया है। आवेदक ने इन मानदंडों के संबंध में अनुक्रमित आंकड़े भी उपलब्ध नहीं कराए हैं।
- v. पाटनरोधी नियमावली का नियम 5(2) यह अधिदेश देता है कि किसी जांच की शुरुआत के लिए आवेदन के समर्थन में साक्ष्य दिया जाएगा। आवेदक ने इस बात का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि पाटन हुआ तथा यह कि घरेलू उद्योग को क्षति उठानी पड़ रही है। इस प्रकार के साक्ष्य न होने की स्थिति में वर्तमान जांच को आरंभ नहीं किया जाना चाहिए था। मक्सिको से पोर्टलैंड सीमेंट के संबंध में डीएस-60 गुआटेमाला – पाटनरोधी जांच में डब्ल्यूटीओ के पैनल और डीएस 264 यूनाइटेड स्टेट्स – कनाडा से साफ्टवुड लंबर पर अंतिम पाटन निर्धारण में पैनल पर विश्वास किया गया है।
- vi. पिछले तीन वर्षों में व्यापार उपचार उपायों के रूप में नए न्यूमैटिक रेडियल टायरों को पर्याप्त संरक्षण उपलब्ध है।
- vii. विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जून, 2020 में संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए प्रतिबंध को वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते समय प्राधिकारी द्वारा ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है।
- viii. पिछले तीन वर्षों में व्यापार उपचार उपायों के माध्यम से नए न्यूमैटिक रेडियल टायरों के लिए पर्याप्त संरक्षण उपलब्ध है।
- ix. घरेलू उद्योग विद्यमान व्यापार उपचार उपायों से पर्याप्त रूप से संरक्षित है और विशेष रूप से डीजीएफटी के निःशुल्क से प्रतिबंधित सूची तक "नए न्यूमैटिक टायरों" को ले जाने के निर्णय के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, 2020 में विचाराधीन उत्पाद के निर्यात घटकर शून्य हो गए हैं।
- x. याचिका में बहुत सी विसंगतियां हैं जिसके परिणामस्वरूप हितबद्ध पक्षकारों को समुचित रूप से खंडन करने के अवसर नहीं मिल रहे हैं। जांच की अवधि 15 माह है जबकि प्रपत्र ज जांच की अवधि के कॉलम में दिए गए आंकड़े वार्षिकीकृत रूप में नहीं हैं।
- xi. याचिका में इस प्रस्तुति कि आयात प्रतिस्थापन बाजार में ही हो रहे हैं, के बावजूद और ओईएम बाजार से संबंधित सूचना अलग करने में घरेलू उद्योग विफल रहा है।
- xii. डीजीएफटी द्वारा हाल के प्रतिबंध मिशलिन सियाम से मिशलिन इंडिया को आपूर्ति और कम करेंगे।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

22. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

23. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे के पर्याप्तता के संबंध में की गई थी, संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों का प्रकट नहीं की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों/अनुरोधों का अगोपनीय पाठ हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल के माध्यम से साक्ष्य/अनुरोधों के अगोपनीय पाठों को परिचालित करने के लिए निदेश देकर एक दूसरे को उपलब्ध कराया।
24. इस तर्क के संबंध में कि संबद्ध जांच की शुरुआत को सही ठहराने के लिए क्षति पहुंचाने वाले पाटन को दर्शाते हुए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया था, यह नोट किया जाता है कि जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में स्वयं प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले संबद्ध वस्तुओं के पाटन का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए जाने के संबंध में उल्लेख था। इस प्रकार, साक्ष्य की समुचितता और स्टीकता का परीक्षण जांच की शुरुआत के पूर्व किया गया था।
25. इस मुद्दे के संबंध में कि घरेलू उद्योग को पर्याप्त संरक्षण उपलब्ध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी/सब्सिडीरोधी शुल्कों की सिफारिश तभी की गई है जब उसके लिए मानदंडों को पूरा किया गया था। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य केवल समान अवसर का सृजन करना और पाटन के क्षतिकारक प्रभाव से घरेलू उद्योग को राहत प्रदान करना है और न कि घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण प्रदान करना है।
26. इस अनुरोध के संबंध में कि विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जून, 2020 में आयातों पर लगाए गए प्रतिबंध से आगे आपूर्ति कम होने जा रही है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं को प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है और उसे आयातों के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया। प्रतिबंधित श्रेणी के उत्पादों के मामले में, आयातकों के लिए इस प्रकार के उत्पाद के आयातों के वास्ते डीजीएफटी से लाइसेंस अथवा अनुमति की आवश्यकता होगी।

ख. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

- 27 धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;

बशर्ते कि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

28. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. आवेदकों ने थाईलैंड के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की कीमत का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। हालांकि, वे लेन-देनवार वास्तविक कीमतों के रूप में संबद्ध वस्तुओं की कीमत की किसी सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाए थे। इस कारण से, आवेदकों ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च से विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर थाईलैंड में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।
- ii. संबद्ध देश से निर्यात कीमत का समायोजन निम्नलिखित खर्च के लिए किया गया है जिसे संबद्ध देशों के निर्यातकों ने भारत को निर्यात करने के लिए वहन किया है अर्थात् समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय ढुलाई और पोर्ट खर्च।
- iii. जैसाकि ऊपर में दिया गया है, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है जिसका ब्यौरा रिकॉर्ड पर आवेदन से देखा जा सकता है। संबद्ध देश से पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तरों से अधिक और महत्वपूर्ण है।
- iv. आवेदक द्वारा मानी गई निर्यात कीमत संशोधित अनुबंधों में प्रकट की गई है। तथापि, याचिका में सीआईएफ कीमत और कारखानागत निर्यात कीमत संबंधी सूचना निहित है तथा हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग द्वारा किए गए सकल समायोजनों से अवगत थे और इसीलिए उन्हें इस बात की जानकारी थी कि वे जिम्मेदार हैं अथवा नहीं।
- v. हितबद्ध पक्षकारों ने वैट कीमत को दर्शाने वाले किसी भी सूचना की मौजूदगी नहीं दर्शाई है जिस पर विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक घरेलू बाजार में उत्पाद की बिक्री करते हैं। एक विवरण देने से पूर्व आवेदकों ने इसके संबंध में आवश्यक जांच की है।
- vi. थाईलैंड में अथवा भारत को विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन, बिक्री, वितरण और विपणन में शामिल कंपनी द्वारा उत्तर प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है और उसके बिना मूल्य श्रृंखला को स्थापित करना संभव नहीं है। निर्यातकों ने पूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए पूरी सूचना प्रस्तुत नहीं की है और इस कारण से उनके उत्तरों को प्राधिकारी की सतत कार्य-पद्धति के अनुसार अस्वीकार किया जाना चाहिए।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

29. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के संबंध में विभिन्न असंगतताएं मौजूद हैं जो आवेदक द्वारा अनुमानित पाटन मार्जिन पर प्रभाव डालती है।
- ii. सामान्य मूल्य की गणना करने के उद्देश्य से थाईलैंड में घरेलू कीमतों का पता लगाने के लिए आवेदक द्वारा किए गए प्रयासों का कोई स्पष्टीकरण नहीं है।
- iii. थाईलैंड एक बाजार अर्थव्यवस्था है जिसके लिए सामान्य मूल्य की संरचना भारत में घरेलू उद्योग की लागत के आधार पर नहीं बनाई जा सकती है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ("अधिनियम") की धारा 9(1) का स्पष्टीकरण (ग) में निर्यात अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने – निर्यातक देश में घरेलू बिक्री कीमत, निर्यातक देश से किसी उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात कीमत अथवा प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों और लाभों के लिए उचित योग के साथ मूल देश में उत्पादन की लागत के लिए तीन विकल्प ही हैं। याचिकाकर्ता द्वारा एकतरफा चौथे विकल्प को अपनाना जो इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं दिया गया है, गैर-कानूनी और इस कारण से अस्वीकार्य है।
- iv. निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में दी गई सूचना पर आधारित होनी चाहिए।
- v. आवेदक द्वारा उस आधार जिस पर कुछ लागतें अपनाई गई थीं, द्वारा कोई सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और इस प्रकार वह डब्ल्यूटीओ, एडीए और भारतीय कानून के अंतर्गत साक्ष्य संबंधी आवश्यकता की जांच में असफल हो गया है।
- vi. प्राधिकारी को वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन का निर्धारण करते समय पीसीएन-वार तुलना को अपनाना चाहिए।
- vii. आवेदक ने निर्यात कीमत में समायोजन के लिए एकपक्षीय रूप से इन आंकड़ों का उपयोग किया है जिसने निर्धारित निर्यात कीमत को अनुचित रूप से कम किया है। समायोजनों के संबंध में इस याचिका में प्रस्तुत किए गए आंकड़े केवल कथन हैं और उसकी साक्ष्य से पुष्टि नहीं की गई है जिस पर इस मामले की शुरुआत करने के लिए विचार नहीं किया जा सकता था।
- viii. याचिकाकर्ताओं ने सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए थाईलैंड में घरेलू कीमतें जानने के लिए किए गए प्रयासों को स्पष्ट नहीं किया है और इसके बजाए भारत में समायोजित उत्पादन लागत पर विश्वास किया है। इस प्रकार के परिकलन की अनुमति बाजार अर्थव्यवस्था के लिए धारा 9(क)1 की व्याख्या (ग) द्वारा अनुमत नहीं है।
- ix. याचिकाकर्ता की निर्यात कीमत परिकलन के संबंध में समायोजनों के लिए साक्ष्य देने में विफलता और समुद्री भाड़ा के संबंध में कोई सूचना न देने के परिणामस्वरूप समुचित रूप से खंडन करने के लिए उत्तरदाता अवसर से वंचित हुआ है।
- x. भारत में उत्पादन लागत के अनुसार सामान्य मूल्य का परिकलन बाजार अर्थव्यवस्था के लिए कानून के तहत अनुमत नहीं है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

30. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना देने के लिए अनुरोध किया गया था। भेजी गई प्रश्नावली के उत्तर में, निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया:

- क. मै. ब्रिजस्टोन एशिया पैसिफिक प्रा. लि. (बीएससीएपी)
- ख. मै. ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाईलैंड) कं. लिमिटेड (बीटीएमटी)
और मै. थाई ब्रिजस्टोन कं. लि. (कम्बाइंड)
- ग. मै. एलएलआईटी (थाईलैंड) कं. लि.
- घ. मै. झोंगसी रबड़ (थाईलैंड) कं. लि.
- ड. मै. सियाम ट्रक रेडियल कंपनी लिमिटेड
- च. मै. डीस्टोन कारपोरेशन लिमिटेड
- छ. मै. मिकेलिन सियाम कं. लि.

31. वर्तमान मामले में पीसीएन-वार तुलना करने के लिए इन हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के संबंध में, कोई वैध अथवा बाध्यकारी तर्क उनके द्वारा नहीं दिया गया है ताकि प्राधिकारी वर्तमान मामले में पीसीएन-वार विश्लेषण पर विचार कर सकें। किसी भी निर्यातक ने वर्तमान मामले में पीसीएन की आवश्यकता को सही ठहराते हुए पर्याप्त तर्क नहीं दिए हैं। इसके अलावा, पीसीएन-वार विश्लेषण का सुझाव देते समय, इन पक्षकारों ने उनके द्वारा सुझाव दिए गए पीसीएन के आधार पर अपनी स्वयं की सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु विगत में पाटनरोधी और सब्सिडीरोधी जांच के अध्यक्षीन रहा है और उन जांचों में प्राधिकारी द्वारा कोई पीसीएन-वार विश्लेषण नहीं किया गया। इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच में पीसीएन-वार विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण से प्राधिकारी ने संपूर्ण रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है।

छ.4 थाईलैंड में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

मै. ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाईलैंड) कं. लिमिटेड (बीटीएमटी) , मै. थाई ब्रिजस्टोन कं. लि. (टीबीसी), और मै. ब्रिजस्टोन एशिया पैसिफिक प्रा. लि. (बीएससीएपी) के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

32. मै. ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाईलैंड) कं. लिमिटेड (बीटीएमटी) , और मै. थाई ब्रिजस्टोन कं. लि. (टीबीसी) ने एकमात्र निर्यातक की प्रश्नावली में दोनों कंपनियों से यह सूचना उपलब्ध कराई है। प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया जाता है कि उनके द्वारा दायर किए गए निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर पूर्ण रूप से अपूर्ण है। दोनों उत्पादकों ने अलग-अलग निर्यातक की प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की है, जो अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान दोनों कंपनियों ने विभिन्न असंबंधित/संबंधित पक्षकारों को घरेलू बाजार में बिक्री की है। हालांकि परिशिष्ट-4क, 4ख और 4 ग में कोई पृथक सूचना नहीं दी गई है। इसके अलावा, परिशिष्ट-6,7,8,9 और 11 इन उत्पादकों द्वारा नहीं उपलब्ध कराया गया है। बीएससीएपी ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में खाली प्रपत्र प्रस्तुत किया है। तदनुसार, प्राधिकारी मै. ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाईलैंड) कं. लिमिटेड, मै. थाई ब्रिजस्टोन कंपनी लि. और मै. ब्रिजस्टोन एशिया पैसिफिक प्रा. लि. द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों को अस्वीकार करते हैं। इस कारण से, इन कंपनियों के लिए सामान्य मूल्य का अनंतिम रूप से निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया जाता है।

एलएलआईटी (थाईलैंड) कं. लि. के लिए सामान्य मूल्य

33. मै. एलएलआईटी (थाईलैंड) कं. लि. ("एलएलआईटी") ने निर्यातक की प्रश्नावली में भारत को अपनी घरेलू बिक्री, निर्यात और उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई है। एलएलआईटी ने घरेलू बाजार में की गई बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। हालांकि बाद के पैराओं में दिए गए कारणों से, एलएलआईटी के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में दी गई सूचना के आधार पर नहीं किया गया है और उसका निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

झोंगसी रबड़ (थाईलैंड) कं. लि.के लिए सामान्य मूल्य

34. मै. झोंगसी रबड़ (थाईलैंड) कं. लि. ने निर्यातक की प्रश्नावली में अपनी घरेलू बिक्री और उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई है। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान कंपनी ने विभिन्न असंबंधित पक्षकारों को घरेलू बाजार में ***मी.टन की बिक्री की है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभकारी घरेलू बिक्री लेन-देन का निर्धारण करने के लिए व्यापार जांच की सामान्य प्रक्रिया आयोजित की। प्राधिकारी ने यह पाया कि लाभप्रद बिक्री *** प्रतिशत से अधिक है और इस प्रकार प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सभी घरेलू बिक्री पर विचार किया है। कंपनी ने वारंटी, छूट और अंतरदेशीय दुलाई के आधार पर समायोजनों का दावा किया है जिसकी अनुमति प्राधिकारी द्वारा दी गई है। तदनुसार, मै. झोंगसी रबड़ (थाईलैंड) कं. लि. के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

मै. सियाम ट्रक रेडियल कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) और डीस्टोन कारपोरेशन लिमिटेड (निर्यातक) के लिए सामान्य मूल्य

35. मै. सियाम ट्रक रेडियल कंपनी लिमिटेड ने निर्यातक की प्रश्नावली में अपनी घरेलू बिक्री और भारत में निर्यात के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है। हालांकि उत्पादन की लागत से संबंधित कोई भी सूचना संगत परिशिष्टों में उपलब्ध नहीं कराई गई है, यद्यपि इसका उल्लेख निर्यातक की प्रश्नावली के विवरण संबंधी भाग में किया गया है कि संगत सूचना प्रस्तुत की गई है। वास्तव में, उत्पादक ने निर्यातक की प्रश्नावली में परिशिष्ट-1,2,3ग, 4क और 4ख में ही उपलब्ध कराया है। इस कारण से प्राधिकारी इस उत्पादक के लिए व्यापार जांच की सामान्य प्रक्रिया पूरा करने के लिए सक्षम नहीं हैं। तदनुसार, सियाम ट्रक रेडियल कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

मै. मिकेलिन सियाम कं. लि.(उत्पादक) और मिकेलिन एशिया पैसिफिक एक्सपोर्ट (एस जी) प्रा. लि. (निर्यातक) के लिए सामान्य मूल्य

36. मै. मिकेलिन सियाम कं. लि. ने निर्यातक की प्रश्नावली में अपनी घरेलू बिक्री के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान कंपनी ने विभिन्न असंबंधित पक्षकारों को घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। हालांकि, परिशिष्ट-6,7 और 8 में दिए जाने के लिए अपेक्षित उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण है। अतः प्राधिकारी इस उत्पादक के लिए व्यापार जांच की सामान्य प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है। तदनुसार, मिकेलिन सियाम कं. लि. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

थाईलैंड के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

37. थाईलैंड के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.5 निर्यात कीमत का निर्धारण

मै. ब्रिजस्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग (थाईलैंड) कं. लिमिटेड (बीटीएमटी) , मै. थाई ब्रिजस्टोन कं. लि. (टीबीसी), और मै. ब्रिजस्टोन एशिया पैसिफिक प्रा. लि. (बीएससीएपी) के लिए निर्यात कीमत

38. जैसाकि ऊपर में उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी बीटीएमटी, टीबीसी और बीएससीएपी द्वारा प्रस्तुत की गई निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर अस्वीकार करते हैं। तदनुसार प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन कंपनियों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण करते हैं।

एलएलआईटी (थाईलैंड) कं. लि. के लिए निर्यात कीमत

39. उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किए उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को 30 प्रतिशत से अधिक निर्यात दुबई आधारित व्यापारियों नामतः मै. अल डोबोई एफजेडई, आईटीआर मिडल ईस्ट एफजेडसीओ और झिनुइम्पेक्स एफजेडई के माध्यम से किया गया है। इन व्यापारियों ने संबद्ध जांच में निर्यातकों की अपनी प्रश्नावली का उत्तर

प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण से, प्राधिकारी एलएलआईटी के उत्तर को स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि भारत को किए गए निर्यातों के एक बड़े हिस्से के लिए पूर्ण निर्यात चेन प्राधिकारी के समक्ष नहीं है। तदनुसार, एलएलआईटी के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

झोंगसी रबड़ (थाईलैंड) कं. लि.के लिए निर्यात कीमत

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. झोंगसी रबड़ (थाईलैंड) कं. लि.ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं का *** मी.टन निर्यात किया है। कंपनी ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय भाड़ा, पोर्ट हैंडलिंग प्रभार और ऋण लागत के आधार पर समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने एक्स-फैक्टरी स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए बैंक प्रभार के कारण भी समायोजन किया है। इस प्रकार से निर्धारित एक्स-फैक्टरी निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

मै. सियाम ट्रक रेडियल कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) और डीस्टोन कारपोरेशन लिमिटेड (निर्यातक) के लिए निर्यात कीमत

41. जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर स्वीकार नहीं करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन कंपनियों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

मै. मिकेलिन सियाम कं. लि.(उत्पादक) और मिकेलिन एशिया पैसिफिक एक्सपोर्ट (एस जी) प्रा. लि. (निर्यातक) के लिए निर्यात कीमत

42. निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तरों से यह नोट किया जाता है कि निर्यातक ने भारत में एक संबंधित पक्षकार अर्थात् मै. मिकेलिन सियाम कं. लि.(एमआईपीएल) को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। एमआईपीएल ने भारत में संबद्ध वस्तुओं की पुनः बिक्री से संबंधित कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। इस खामी और इन कंपनियों के लिए सामान्य मूल्य के भाग में ऊपर में उल्लेख किए गए अन्य तथ्यों को देखते हुए, प्राधिकारी इन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर स्वीकार नहीं करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन कंपनियों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

थाईलैंड से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

43. थाईलैंड के अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण इस नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.6 पाटन मार्जिन

44. ऊपर में किए गए निर्धारण के अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन नीचे दिया गया है:

| | सामान्य मूल्य (यूएस डा./मी.टन) | निर्यात कीमत (यूएस डा./मी.टन) | पाटन मार्जिन | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----|---------|
| | | | राशि (यूएस डा./मी.टन) | % | रेंज |
| झोंगसी रबर (थाईलैंड) कं. लि. | *** | *** | *** | *** | 10%-30% |
| कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक | *** | *** | *** | *** | 20%-40% |

45. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन अत्यधिक और संबद्ध देश से किए गए निर्यातों के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।

च. क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

46. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- i. संबद्ध वस्तुओं की मांग/स्पष्ट खपत में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
 - ii. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में स्वतंत्र और सापेक्ष दोनों रूपों में बहुत हद तक वृद्धि हुई है।
 - iii. संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में कटौती हो रही है और कीमत में कटौती बहुत अधिक हद तक सकारात्मक है।
 - iv. उत्पादन की लागत और बिक्री कीमत की तुलना यह दर्शाती है कि यद्यपि बिक्री कीमत में भी वृद्धि हुई है, यह वृद्धि उत्पादन की लागत में वृद्धि से कम है। इन आयातों के कारण कीमत न्यूनीकरण हो रहा है।
 - v. बढ़ती हुई मांग पर विचार करते हुए, घरेलू उद्योग की क्षमता में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तदनुसार, उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई। हालांकि घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री उस सीमा से कम है जो पाटन आयातों के न रहने की स्थिति में हो सकती थी जिसमें बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है।
 - vi. घरेलू उद्योग के लाभ में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है। नकद लाभ, पीबीआईटी और आरओसीई में भी बहुत हद तक गिरावट आई है और वह क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक हद तक कम हो गई है।
 - vii. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में चीन से आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को देखते हुए वृद्धि होनी चाहिए थी परंतु इसके विपरीत इसके कमी आई है।
 - viii. घरेलू उद्योग के पास मालसूची के स्तर में क्षति की अवधि के दौरान कमी आई है लेकिन वह बहुत अधिक है।
 - ix. रोजगार और मजदूरी में क्षति की अवधि में सुधार हुआ है। याचिकाकर्ता अन्य वस्तुओं का भी उत्पादन करते हैं और इस कारण से रोजगार और मजदूरी एकमात्र संबद्ध वस्तुओं के कार्य-निष्पादन पर निर्भर नहीं है।
 - x. जैसाकि यह सूचना दर्शाएगी, जबकि उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है, आयात की कीमतें घरेलू कीमतों की तुलना में बहुत कम थी और इस कारण से इसने घरेलू उद्योग को लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतें बढ़ाने से रोका।
 - xi. पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है बल्कि वास्तविक भी है। घरेलू उद्योग पर पाटन का प्रभाव प्रतिकूल है।
 - xii. अधिकांश मानदंडों जैसे लाभ, निवेश पर लाभ, नकद लाभ आदि के संदर्भ में घरेलू उद्योग का विकास नकारात्मक है।
 - xiii. चीन ने थाईलैंड में ट्रक और बस रेडियल टायरों के लिए बहुत अधिक निवेश किया है।
 - xiv. चीन में सबसे बड़े टायर उत्पादकों में से एक उत्पादक, शानडोंग लिंगलॉग टायर कंपनी ने एक नए रेडियल ट्रक और बस निर्माण करने वाले संयंत्र में बहुत अधिक निवेश किया है। थाईलैंड में यह संयंत्र लिंगलॉग की चौथी घरेलू निर्माण सुविधा है जो अपनी पूरी क्षमता से एक वर्ष में 2.4 मिलियन ट्रक और बस के टायरों का उत्पादन करेगी और आगे थाईलैंड में पहले से उपलब्ध अधिशेष संख्या में वृद्धि करेगी।

कंपनी की क्षमता मात्र भारत में मिश्रित क्षमता से अधिक है। यह स्पष्ट रूप से इस तरीके को दर्शाता है जिसमें चीन की कंपनियां चीन से बाहर निवेश कर रही हैं जिससे कि उनके विरुद्ध व्यापार बचाव मामलों में वृद्धि से आगे निकला जा सके।

- xv. थाईलैंड से संबद्ध वस्तुओं के आयात बहुत कम समय के भीतर विशेषकर चीन की संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने के बाद तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा, यह निर्यात बाजारों को लक्षित करने के उद्देश्य से थाईलैंड में क्षमताओं में वृद्धि के भारत में बहुत अधिक मात्रा में आयातों का द्योतक है जो पाटनरोधी शुल्कों को नहीं लगाए जाने की स्थिति में आगे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे को दर्शाता है।
- xvi. वैश्विक रूप से अनेक देशों द्वारा चीन के टायरों पर पाटनरोधी अथवा सब्सिडीरोधी शुल्कों को लगाने से चीन के उत्पादकों को चीन से बाहर के देशों में निवेश करना पड़ा है। चीन का थाईलैंड में निवेश कुछ वर्षों के दौरान धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। थाईलैंड के निवेश के बोझ से आंकड़ों के अनुसार थाईलैंड में चीन का प्रत्यक्ष निवेश कुल 28 बिलियन बाहट (लगभग 800 मिलियन डालर) है जो इसे थाईलैंड में तथा सबसे बड़ा निवेशक बनाता है।
- xvii. शांगडोंग लिंगलोंग टायर कंपनी ने 2012 में थाईलैंड में पहले ही पहले चरण का निवेश किया है अर्थात् रेडियल ट्रक के टायरों के लिए उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने में 700 मिलियन यूएस डालर (24.5 बिलियन बाहट) के निवेश में 2016 में दूसरे चरण का निवेश और प्राकृतिक रबड़ के लिए उत्पादन सुविधाओं की स्थापना के लिए निवेश किया है। कंपनी ने अपनी कॉरपोरेट फाइलिंग में रेडिएल ट्रक टायरों के लिए वार्षिक क्षमता में 800,000 यूनिटों, रेडिएल पैसेंजर टायरों की 2 मिलियन इकाइयों और 400,000 बायस-प्लाई टायरों के लिए क्षमता में वृद्धि करने की योजना का खुलासा किया है। यह निर्माण 18 महीने में होने की आशा है। यह निवेश का तीसरा चरण हो सकता है और निवेश के दूसरे चरण का हिस्सा हो सकता है। इसके फलस्वरूप, भारत सहित विभिन्न देशों को थाईलैंड से टायरों का बहुत अधिक निर्यात हुआ है।
- xviii. थाईलैंड से भारत को निर्यात कीमत थाईलैंड से अन्य देशों को निर्यात कीमत की तुलना में बहुत कम है। थाईलैंड से निर्यातों में उन बाजारों में वृद्धि हुई है जहां चीन के उत्पाद पर व्यापार उपचार शुल्क लग रहा है।
- xix. वर्तमान जांच में चीनी पाटित सामान नए स्रोत में चले गए हैं और इस प्रकार घरेलू उद्योग कुछ मानदंडों के संबंध में सुधार दर्शाता है। इसी विनियम इसे विशेष रूप से क्षति दर्शाने वाले कारक के रूप में मानता है। इसी द्वारा बेलारूस के मूल के पॉलीस्टर स्टेपल फाइबर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का इस संबंध में उल्लेख किया गया है।
- xx. घरेलू उद्योग द्वारा कम लाभप्रद निर्यातों की बिक्री में वृद्धि भी घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत है।
- xxi. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति संबंधी सूचना की चुनिंदा तुलना करना त्रुटिपूर्ण है। यह सूचना पूरी क्षति अवधि में ध्यान में रखी जानी चाहिए थी। इसी - ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग्स में डब्ल्यूटीओ पैनल की रिपोर्ट का इस संबंध में उल्लेख किया गया है।
- xxii. वर्तमान क्षति की अवधि में चीन से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के लिए मानी गई जांच की अवधि और सीवीडी जांच की अवधि शामिल है। घरेलू उद्योग को पाटनरोधी और प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने के बाद कुछ सुधार के बावजूद पूरी तरह से अभी ठीक होना है।
- xxiii. पाटित आयात 2016-17 में ऊंचाई पर थे और आयात उसके बाद चीन पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने और चीन के संबंध में सीवीडी जांच शुरू करने से कम हुए। इस प्रकार, निष्पादन में सुधार लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के उपायों के परिणामस्वरूप थे।

- xxiv. एनआईपी से अलग सामान्य मूल्य का परिकलन करने के लिए भी निदेशालय द्वारा आदर्श लागत माने जाने के परिणामस्वरूप सामान्य मूल्य में कमी हो सकती है। सामान्य मूल्य का परिकलन प्रश्नावली के उत्तर में निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर किया जा सकता है।
- xxv. भारतीय उद्योग में भारत में मांग की कमी पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है। मांग-आपूर्ति अंतराल के कारण पाटन का औचित्य नहीं बनाया जा सकता। डीसीएम इडेमिस्तु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेसटेट के निर्णय को इस संबंध में देखा जा सकता है।
- xxvi. घरेलू उद्योग अब भी चीन से पाटित आयातों के विगत कुप्रभावों से ठीक होने की प्रक्रिया में है और इस प्रकार उस स्थिति से जब आयात थाइलैंड से भारत में बहुत कम थे, से तुलना करना सही तस्वीर नहीं दर्शाएगा।
- xxvii. "ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाइलैंड) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी" में सेसटेट निर्णय का उल्लेख करना वर्तमान मामले में विभेदक कारकों के कारण प्रतिकूल है।
- xxviii. घरेलू उद्योग में क्षति का एक मात्र कारण पाटन को मानना हितबद्ध पक्षकारों की ओर से गलत है। सेसटेट की वार्षिक रिपोर्ट भी पाटन और सब्सिडीकृत आयातों के पूर्व कुप्रभावों से उद्योग के ठीक होने की स्थिति पर जोर डालती है। इसके अतिरिक्त, वार्षिक रिपोर्टों पर विश्वास करना गलत बताया गया है क्योंकि क्षति की अवधि और वार्षिक रिपोर्टों के बजाए विशेष अवधि पर वार्षिक रिपोर्टों के जोर का संबंध समग्र प्रचालनों आदि के संबंध में है।
- xxix. क्षति पहुँचाने वाले अन्य कारकों की मौजूदगी संबद्ध देश से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच आवश्यक रूप से कारणात्मक संपर्क नहीं तोड़ती। थाइलैंड - पौलैंड से लौह अथवा नॉन अलॉय स्टील और एच-बीम्स के एंगल, शेप और सेक्शनों पर पाटनरोधी शुल्क में डब्ल्यूटीओ पैनल की रिपोर्ट पर इस संबंध में विचार किया जाता है।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

47. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. थाइलैंड से आयातों में 2017-18 के बाद ही वृद्धि हुई है। सितंबर, 2017 में, चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयात के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। तब 2018 में चीन जन.गण. से उसी वस्तुओं के विरुद्ध सब्सिडीरोधी जांच देखी। तदनुसार, चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयात समाप्त हो गए और उसका कुछ हिस्सा थाइलैंड को चला गया।
- ii. भारतीय मांग, भारतीय उत्पादन और घरेलू बिक्री की तुलना में संबद्ध वस्तुओं के आयातों के बार में आंकड़ों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि भारतीय उद्योग का हिस्सा बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ था।
- iii. थाइलैंड से आयातों में यह वृद्धि चीन जन.गण. से आयातों के न्यूनीकरण के उत्तर में थी। थाइलैंड से आयात की कमी भी घरेलू उत्पादन से प्रतिस्पर्धा नहीं रही है जिसमें चीन के आयातों द्वारा गंवाए गए बाजार को भी प्राप्त कर लिया है।
- iv. भाग लेने वाली भारतीय कंपनियां चीन जन.गण. के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद काफी हद तक अपनी बिक्री कीमत को बढ़ाने में सक्षम थीं। चीन जन.गण. पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से भाग लेने वाली भारतीय कंपनियों द्वारा सामना की गई कीमत हास/न्यूनीकरण मुक्त हो गया।
- v. कम कीमत पर बिक्री जैसे ही उसे स्थापित किया गया है, क्षति की सीमा का माप करने का एक उपकरण है और न कि क्षति का आकलन करने के लिए एक कारक है। पाटनरोधी नियमावली विशेषरूप से कम कीमत पर बिक्री के किसी उल्लेख को शामिल नहीं करती है।
- vi. ऐसा प्रतीत होता है कि जांच की अवधि में भाग लेने वाली कंपनियों को कोई क्षति नहीं हुई है। वास्तव में, चीन जन.गण. से आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि

भाग लेने वाली कंपनियों के आर्थिक कार्य-निष्पादन में मात्रा के मामलों में तथा कीमत और लाभप्रदता संबंधी मानदंडों के मामले में सुधार हुआ है।

- vii. घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा, क्षमता और उत्पादन की मात्रा में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक सुधार हुआ है। भाग लेने वाली कंपनियों की बिक्री में, घरेलू और निर्यात बाजारों दोनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जाती है।
- viii. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक लाभ अर्जित किया है और यह पिछले वर्ष में इसकी प्रति इकाई पीबीआईटी से तीन गुना अधिक हुआ है। उसी प्रकार से, घरेलू बिक्री के लिए नकद लाभ में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है। 2017-18 में गिरावट के बाद, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग का बहुत अधिक हद तक नकद लाभ हुआ है।
- ix. घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, का कारण अन्य कारकों जैसे एनबीएफसी संकट, ऑटोमोबाइल उद्योग में मंदी, भारत में बीमा और ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। इन कारकों के बावजूद, भाग लेने वाली कंपनियों ने बहुत अधिक विस्तार किया है और लाभ अर्जित किया है जिसे 2018-19 के लिए सीएट की वार्षिक रिपोर्ट और प्रबंधन विश्लेषण रिपोर्ट से देखा जा सकता है।
- x. वर्तमान याचिका में जांच की अवधि 15 महीने लंबी है। हालांकि, प्रपत्र एच में जांच की अवधि कॉलम के अंतर्गत घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े वार्षिकीकृत रूप में नहीं हैं। यह सही स्थिति को नहीं दर्शाता है और पिछले क्षति वर्षों जो 12 महीने लंबे हैं, से तुलना करने में कठिनाई उत्पन्न करता है।
- xi. घरेलू उद्योग ने गलत मूल सीमा शुल्क पर विचार कर कीमत में कटौती की सही गणना नहीं की है।
- xii. यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध वस्तुओं के आयात पर शुल्क लगाते हैं तब यह संबद्ध वस्तुओं के प्रयोक्ताओं को घरेलू उद्योग पर पूर्ण रूप से निर्भर करने के लिए बाध्य कर सकता है और यह घरेलू उद्योग को अन्यायोचित संरक्षण प्रदान करेगा।
- xiii. घरेलू उद्योग पुष्टि न किए गए कथन से परे क्षति रहित कीमत की गणना के संबंध में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा पाया है कि “संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमतें क्षति रहित कीमत के स्तर से कम हैं”। एनआईपी की रेंज इस संबंध में डीजीटीआर द्वारा दिए गए स्पष्ट अधिदेश के बावजूद नहीं दी गई है।
- xiv. थाइलैंड से मिसिलिन के आयातों और घरेलू उद्योग की बिक्री में कमी के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि मिसिलिन ब्रांड टायर बाजार में अलग-अलग/प्रीमियम कीमतों पर रखा गया है।
- xv. थाइलैंड से आयातों की मात्रा में वृद्धि मांग-आपूर्ति अंतराल को पूरा करने के लिए थी, जो चीन से आयातों के परिणामस्वरूप कम हुआ था। थाइलैंड से यह मात्रा पूरी क्षति अवधि में 0-10 प्रतिशत की रेंज में रही है।
- xvi. कीमत कटौती और क्षति संबंधी मानदंडों, यथा – नकद लाभ और कुल लाभप्रदता के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त, कोई कीमत न्यूनीकरण नहीं है। घरेलू उद्योग की बिक्री, क्षमता और उत्पादन गुणवत्ता में जांच की अवधि में काफी सुधार हुआ है। कोई वास्तविक क्षति नहीं है।
- xvii. नकद लाभ, पीबीआईटी और आरओसीई के संबंध में क्षति की मौजूदगी चीन से आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पूर्व की अवधि के निमित्त है।
- xviii. ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाइलैंड) बनाम घरेलू उद्योग में सेसटेट ने गलत आधारभूत सीमा शुल्क मानकर कीमत कटौती गलत परिकलित की है।
- xix. मिशलिन से निर्यातों के कारण क्षति नहीं हो रही है क्योंकि ये निर्यात भारत में वार्षिक ट्रक टायर बाजार की तुलना में नगण्य हैं। इसे इस तथ्य से और स्पष्ट किया जा सकता है कि मिशलिन चीन से मिशलिन भारत को निर्यातों में वर्तमान पाटनरोधी शुल्क लगने के बावजूद प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है।

- xx. थाइलैंड से निर्यातों और घरेलू टायरों की तुलना में मिशलिन टायरों की प्रीमियम कीमत, निष्पादन और शक्तिशाली ब्रांड तथा नवीनता के कारण घरेलू उद्योग को क्षति और थाइलैंड से निर्यातों के बीच कारणात्मक संपर्क का अभाव है। ये बातें प्राधिकारी के समक्ष लिखित अनुरोध में दिए गए पत्र से लाई गई थीं।
- xxi. प्राधिकारी को नियम 11 के अनुसार, घरेलू उद्योग को क्षति का खतरा, कारणात्मक संपर्क और समान वस्तुओं के घरेलू बाजार में कीमत पर प्रभाव निर्धारित करना चाहिए। वर्तमान जांच में ये तीनों नहीं हैं। मिशलिन ब्रांड के टायर घरेलू निर्माताओं की कीमतों की तुलना में 17-22 प्रतिशत अधिक कीमत पर बेचे गए थे।
- xxii. घरेलू उद्योग के निष्पादन में 2017-18 के दौरान और जांच की अवधि के दौरान आयातों में सबसे अधिक उछाल के बावजूद काफी सुधार हुआ।
- xxiii. जापान से कुछ हॉट रोलड स्टील उत्पादों पर पाटनरोधी उपाय में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट प्राधिकारी के सभी ज्ञात कारकों तथा उन अन्य कारकों जिनके कारण पाटित आयात नहीं हुए हैं, द्वारा क्षति की जांच करने का दायित्व दर्शाती है। चीन जन. गण., पोलैंड, रूस और रोमानिया से बाल बियरिंग (50 एमएम बोर डायामेटर तक); मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड, सऊदी अरब और चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नॉन-वूवन फैब्रिक; और चीन जन. गण. से निर्यातित बेल्डिंग फैब्रिक के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांचों में अंतिम जांच परिणाम भी इस संबंध में उल्लिखित किए गए हैं। इन जांच परिणामों में प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति नहीं हुई।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

48. प्राधिकारी ने इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विधिवत् विचार करने के बाद इस नियमावली के अनुसार विभिन्न मानदंडों की जांच की है।
49. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव और पाटित आयातों की मात्रा; और (ख) इस प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणाम प्रभाव, दोनों की वस्तुपरक जांच का प्रावधान है। पाटित आयातों की मात्रा संबंधी प्रभाव के बारे में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या पाटित आयातों में या तो स्वतंत्र रूप में या भारत में उत्पाद अथवा खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत संबंधी प्रभाव के बारे में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा बहुत अधिक हद तक कीमतों पर दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाएगी जो अन्यथा काफी हद तक हुई होती।
50. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (IV) में निम्नानुसार उल्लेख है:
- "संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"*
51. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए कुल सूचकांकों जिनका इस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन का परिमाण और मार्जिन आदि पर विचार किया गया है।

छ.4 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव

52. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II (ii) निम्नलिखित प्रावधान है:

“पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।”

क) मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

53. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से भारत में इस उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

| विवरण | यूओएम | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | जांच की अवधि | |
|------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------|-------------|
| | | | | | वास्तविक | वार्षिकीकृत |
| संबद्ध देश | मी.टन | 3,514 | 2,720 | 9,623 | 27,697 | 22,158 |
| अन्य देश | मी.टन | 75,790 | 91,292 | 50,152 | 20,798 | 16,638 |
| घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री | मी.टन | 348,576 | 356,975 | 404,935 | 603,824 | 483,059 |
| अन्य भारतीय उत्पादक | मी.टन | 54,081 | 43,631 | 44,143 | 21,240 | 16,992 |
| कुल मांग | मी.टन | 481,961 | 494,619 | 508,854 | 673,559 | 538,847 |

ख) स्वतंत्र तथा सापेक्ष रूप में आयात

54. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस पर विचार करें कि क्या या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में संबद्ध देश से पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

| विवरण | यूओएम | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | जांच की अवधि | |
|----------------|-------|---------|---------|---------|--------------|-------------|
| | | | | | वास्तविक | वार्षिकीकृत |
| आयात की मात्रा | | | | | | |
| संबद्ध देश | मी.टन | 3,514 | 2,720 | 9,623 | 27,697 | 22,158 |
| अन्य देश | मी.टन | 75,790 | 91,292 | 50,152 | 20,798 | 16,638 |
| चीन जन.गण | मी.टन | 69,805 | 85,902 | 42,501 | 14,839 | 11,871 |
| अन्य | मी.टन | 5,984 | 5,390 | 7,652 | 5,959 | 4,767 |
| कुल | मी.टन | 79,304 | 94,013 | 59,776 | 48,495 | 38,796 |

| विवरण | यूओएम | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | जांच की अवधि | |
|---|-------|---------|---------|---------|--------------|-------------|
| आयात की मात्रा | | | | | वास्तविक | वार्षिकीकृत |
| निम्नलिखित की तुलना में संबद्ध देश से आयात | | | | | | |
| भारतीय उत्पादन | % | 0.79% | 0.60% | 1.88% | 3.67% | 3.67% |
| खपत | % | 0.73% | 0.55% | 1.89% | 4.11% | 4.11% |
| कुल आयात | % | 4.43% | 2.89% | 16.10% | 57.11% | 57.11% |

55. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि:

- क) संबद्ध देश से आयातों में पिछले वर्षों की तुलना में स्वतंत्र रूप में जांच की अवधि के दौरान (वार्षिकीकृत) बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है।
- ख) अन्य देशों से आयातों में गिरावट आई है। ये नोट किया जाता है कि चीन जन.गण. से आयातों में पाटनरोधी शुल्क और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने के बाद बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है। हालांकि संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि हुई है।
- ग) आयातों में भारत में उत्पादन तथा खपत की तुलना में वृद्धि हुई है।
- ग) **मांग में बाजार हिस्सा**

56. मांग में संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा आधार वर्ष में प्रायः नगण्य है और उसमें जांच की अवधि के दौरान (वार्षिकीकृत) वृद्धि हुई है।

| मांग में बाजार हिस्सा | यूओएम | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | जांच की अवधि | |
|------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------|-------------|
| | | | | | वास्तविक | वार्षिकीकृत |
| संबद्ध देश | % | 0.7% | 0.5% | 1.9% | 4.1% | 4.1% |
| अन्य देश | % | 15.7% | 18.5% | 9.9% | 3.1% | 3.1% |
| घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री | % | 72.3% | 72.2% | 79.6% | 89.6% | 89.6% |
| अन्य भारतीय उत्पादक | % | 11.2% | 8.8% | 8.7% | 3.2% | 3.2% |
| कुल | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

छ.5 भारतीय उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

57. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, इस नियमावली के अनुबंध II(ii) में निम्नलिखित उल्लेख है:-

“नियम 18 के उप नियम (2) में यथा संदर्भित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी इस पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमतों पर अन्यथा काफी हद तक दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाएगी जो अन्यथा काफी हद तक हुई होती।”

58. तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत हास/ कीमत न्यूनीकरण और कम कीमत पर बिक्री के संबंध में की गई है।

क) **कीमत में कटौती**

59. कीमत में कटौती के विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुंच मूल्य से की गई है। तदनुसार, संबद्ध देश से पाटित आयातों के कटौती संबंधी प्रभावों को नीचे दिए गए अनुसार निर्धारित किया गया है:

| विवरण | यूओएम | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | जांच की अवधि |
|----------------------|----------------|---------|---------|---------|--------------|
| आयातों की पहुंच कीमत | रु./ किग्रा | 170 | 147 | 149 | 168 |
| निवल बिक्री प्राप्ति | रु./ किग्रा | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 95 | 97 | 101 |
| कम कीमत पर बिक्री | रु./ किग्रा | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 136 | 142 | 114 |
| कम कीमत पर बिक्री | % | *** | *** | *** | *** |
| | रेंज | 10-30 | 20-40 | 20-40 | 10-30 |

60. यह देखा जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत जांच की अवधि सहित क्षति की जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से पाटित आयातों द्वारा की जा रही कीमत में कटौती को दर्शाते हुए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कीमत में कटौती का स्तर घरेलू उद्योग पर कीमत संबंधी प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण है।

ख) **कीमत न्यूनीकरण और हास**

61. इस बात का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों द्वारा दबाव पैदा किया जा रहा है और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से बहुत अधिक हद तक कीमतों पर दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाएगी जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक हुई होती, आयातों की पहुंच कीमत की तुलना में क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन पर विचार किया गया है और वे निम्नानुसार हैं:

| विवरण | इकाई | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | जांच की अवधि |
|----------------|-------------|---------|---------|---------|--------------|
| बिक्री की लागत | रु./किग्रा. | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 98 | 104 | 109 |
| बिक्री की कीमत | रु./किग्रा. | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 96 | 97 | 101 |
| पहुंच कीमत | रु./किग्रा. | 170 | 147 | 149 | 168 |
| | सूचीबद्ध | 100 | 86 | 88 | 99 |

62. यह देखा जाता है कि बिक्री की लागत और बिक्री कीमत दोनों में जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। हालांकि, आयात की कीमतों में उसी अवधि के दौरान गिरावट आई है। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बिक्री की लागत में 9 सूचकांक तक वृद्धि हुई जबकि उसी अवधि के दौरान बिक्री कीमत में 1 सूचकांक तक वृद्धि हुई। यह भी देखा जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत क्षति की पूरी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागत का स्तर और बिक्री कीमत से कम रहा है। इस प्रकार, आयातों का घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है।

ग) **कम कीमत पर बिक्री**

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर कम कीमत पर बिक्री संबंधी प्रभाव हुआ है:

| विवरण | इकाई | जांच की अवधि |
|--------------------|------------|--------------|
| आयात की पहुंच कीमत | र./किग्रा. | 168 |
| क्षति रहित कीमत | र./किग्रा. | *** |
| कम कीमत पर बिक्री | र./किग्रा. | *** |
| कम कीमत पर बिक्री | % | *** |
| कम कीमत पर बिक्री | रेंज % | 10%-30% |

मात्रा संबंधी प्रभाव और कीमत संबंधी प्रभाव पर टिप्पणी

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्वतंत्र रूप में और भारत में उत्पादन और खपत की तुलना दोनों में पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इन आयातों के कारण घरेलू कीमतों में बहुत अधिक हद तक कटौती हो रही है और इसके कारण घरेलू उद्योग के लिए कीमत न्यूनकारी प्रभाव भी उत्पन्न हो रहा है। आयातों की पहुंच कीमत जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत के स्तर से बहुत अधिक हद तक नीचे रही है।

छ.6 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर प्रभाव

65. इस नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि ऐसे आयातों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का वस्तुपरक जांच शामिल होगी। पाटनरोधी नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है।

क) **उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता का उपयोग**

66. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री, और क्षमता का उपयोग नीचे तालिका में दिया गया है:

| विवरण | इकाई | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | जांच की अवधि | |
|--------------|-------|---------|---------|---------|--------------|-------------|
| | | | | | वास्तविक | वार्षिकीकृत |
| क्षमता | मी.टन | 464,654 | 480,431 | 536,322 | 813,066 | 650,453 |
| उत्पादन | मी.टन | 388,152 | 408,089 | 468,124 | 733,743 | 586,994 |
| क्षमता उपयोग | % | 83.54 | 84.94 | 87.28 | 90.24 | 90.24 |
| घरेलू बिक्री | मी.टन | 348,576 | 356,975 | 404,935 | 603,824 | 483,059 |

67. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने क्षति की पूरी अवधि के दौरान क्षमता में वृद्धि की है। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता में वृद्धि हुई है।

ख) लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

68. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर लाभ और नकद लाभ नीचे तालिका में दिया गया है:

| विवरण | इकाई | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | जांच की अवधि | |
|------------|-----------|---------|---------|---------|--------------|-------------|
| | | | | | वास्तविक | वार्षिकीकृत |
| लाभ/(हानि) | लाख रु. | *** | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 76 | 57 | 83 | 67 |
| लाभ | रु./मी.टन | *** | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 74 | 49 | 48 | 48 |
| पीवीआईटी | लाख रु. | *** | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 79 | 62 | 93 | 74 |
| | रु./मी.टन | *** | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 77 | 54 | 54 | 54 |
| नकद लाभ | लाख रु. | *** | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 85 | 77 | 116 | 93 |
| | रु./मी.टन | *** | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 83 | 66 | 67 | 67 |
| आरओसीई | % | *** | *** | *** | *** | *** |
| | रेंज | 10%-30% | 0%-20% | 0%-20% | 0%-20% | 0%-20% |

69. यह नोट किया जाता है कि:

घरेलू उद्योग के लाभ में 2017-18 तक कमी आई और उसके बाद जांच की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई। जबकि, 2017-18 की तुलना में जांच की अवधि में लाभ में सुधार हुआ है, अभी भी वे 2015-16 और 2016-17 की तुलना में कमतर हैं। आरओसीई की भी वही प्रवृत्ति रही है। हालांकि पीबीआईटी और लाभ प्रति मी.टन में सतत रूप से गिरावट आई है।

ग) रोजगार, वेतन और उत्पादकता

70. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की रोजगार और उत्पादकता नीचे तालिका में दी गई है:

| विवरण | इकाई | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | POI | जांच की अवधि(वार्षिकीकृत) |
|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|-------|---------------------------|
| कर्मचारियों की संख्या | संख्या | *** | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 104 | 104 | 103 | 103 |
| वेतन | लाख रु. | *** | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 114 | 133 | 215 | 172 |
| प्रति दिन उत्पादकता | मी.टन/दिन | 1,078 | 1,134 | 1,300 | 1,631 | 1,631 |

71. यह देखा गया है कि कर्मचारियों की संख्या 2016-17 तक बढ़ी, फिर 2017-18 में समान रही और उसके बाद जांच की अवधि में गिरावट आई। उत्पादकता में क्षति की जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

घ) मालसूची

72. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

| विवरण | इकाई | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | जांच की अवधि |
|-------|----------|---------|---------|---------|--------------|
| औसत | मी.टन | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 101 | 92 | 184 |

73. यह देखा गया है कि मालसूची में 2016-17 में वृद्धि हुई और फिर 2017-18 में उसमें गिरावट आई और उसके बाद जांच की अवधि में वृद्धि हुई।

ड.) वृद्धि

| विवरण | इकाई | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | जांच की अवधि-वार्षिकीकृत |
|---------|------|---------|---------|---------|--------------------------|
| वृद्धि | | | | | |
| उत्पादन | % | - | *** | *** | *** |

| | रेंज | | 0%-20% | 10%-30% | 20%-40% |
|----------------|------|---|-------------|-------------|---------|
| घरेलू बिक्री | % | - | *** | *** | *** |
| | रेंज | | 0%-20% | 10%-30% | 10%-30% |
| पीबीटी - घरेलू | % | - | *** | *** | *** |
| | रेंज | | (20)%-(40)% | (20)%-(40)% | 10%-30% |
| नकद लाभ | % | - | *** | *** | *** |
| | रेंज | | 0%-(20)% | 0%-(20)% | 20%-40% |
| आरओसीई | % | - | *** | *** | *** |
| | रेंज | | 0%-(20) % | 0%-(20) % | 0%-20% |

74. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने चीन जन.गण. के विरुद्ध पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने के बाद जांच की अवधि के दौरान मात्रा तथा कीमत संबंधी मानदंडों में वृद्धि देखी है।

च.) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

75. घरेलू उद्योग क्षति की जांच की अवधि के दौरान पूंजी निवेश करता रहा है।

छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

76. संबद्ध देश से आयात कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों को छोड़कर उन कारकों जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, आदि की जांच यह दर्शाती है कि संबद्ध देश से आयात किए गए माल का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और उत्पादन लागत से कम है जिसके कारण भारतीय बाजार में कीमत में बहुत अधिक कटौती तथा कीमत न्यूनीकरण हो रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि दर्शा रही थी और इस कारण से वह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं हो सकता था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आयातों के कारण संबद्ध वस्तुओं की घरेलू कीमतों पर प्रभाव पड़ रहा है।

च.7 क्षति और क्षति मार्जिन का परिमाण

77. घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण अनुबंध III के साथ पठित इस नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया गया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत का निर्धारण जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति रहित कीमत की तुलना क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत से की गई है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। वही बर्ताव यूटिलिटी के साथ किया गया है। क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। जांच की अवधि में उत्पादन की गणना सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर विचार करते हुए की गई है और उसके उत्पादन पर प्रति यूनिट निर्धारित लागत तय करने के लिए विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई असाधारण अथवा गैर-आवर्ती खर्च उत्पादन की लागत में नहीं जोड़ा गया था। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित लाभ (22 प्रतिशत कर पूर्व की दर से) की अनुमति सतत कार्य-पद्धति के अनुसार अनुबंध-III में यथा-निर्धारित एनआईपी पर पहुंचने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में दी गई थी। इस प्रकार से निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमतों के साथ नीचे दिए गए अनुसार की गई है:

| विवरण | एनआईपी | पहुंच मूल्य | क्षति मार्जिन | | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----|--------|
| | यूएसडा./मी.टन | यूएसडा./मी.टन | मूल्य | % | रेंज |
| झोंगसी रबर (थाईलैंड) कं. लि. | *** | *** | *** | *** | 10-30% |
| कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक | *** | *** | *** | *** | 20-40% |

ज. पाटन पर क्षति निष्कर्ष

78. वास्तविक क्षति के संबंध में विभिन्न मानदंडों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:
- संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में स्वतंत्र और सापेक्ष रूप में वृद्धि हुई है।
 - संबद्ध वस्तुओं के कारण भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।
 - क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है।
 - लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर लाभ 2017-18 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान सुधार हुआ है लेकिन 2015-16 और 2016-17 में प्राप्त स्तरों से यह कम है।
 - थाईलैंड से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री की लागत से कम है।

झ. अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध

79. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों को छोड़कर किसी ज्ञात कारकों जो उसी समय में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, की जांच करें ताकि इन अन्य कारकों के द्वारा हुई क्षति के लिए पाटित आयातों की जिम्मेदारी नहीं माना जा सके। ये कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं, में अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेची गई आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य-निष्पादन तथा उत्पादकता शामिल है। नीचे यह भी जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान हो सकता था।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

80. अन्य देशों (चीन जन.गण. को छोड़कर) से आयात कम मात्रा में हुआ है और वह थाईलैंड से आयात की कीमत की तुलना में अधिक कीमत पर हुई है। इसके अलावा, चीन जन.गण. से आयातों पर पहले से ही पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लग रहा है। इस प्रकार, किसी अन्य तीसरे देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है।

ख) मांग में संकुचन

81. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में क्षति की समग्र अवधि के दौरान सतत् रूप से वृद्धि हुई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को क्षति मांग में संकुचन के कारण नहीं हुई थी।

ग) प्रौद्योगिकी का विकास

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच ने इस उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में किसी वास्तविक परिवर्तन को नहीं दर्शाया है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

घ) कंपनी के अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन

83. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादन का कार्य-निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का एक संभावित कारण प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने अपनी जांच में विचाराधीन उत्पादन के लिए केवल सूचना पर विचार किया है।

ड.) व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

84. घरेलू उत्पादक संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से प्रतिस्पर्धा करते हैं। घरेलू उद्योग की कीमत काफी हद तक संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत से प्रभावित होती है। इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों को जून, 2020 के बाद से प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है।

च) निर्यात कार्य निष्पादन

85. प्राधिकारी ने अपनी जांच में घरेलू उद्योग के घरेलू कार्य-निष्पादन पर ही विचार किया है।

क्षति और कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष

86. जबकि इस नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों द्वारा पहुंचाई जा रही क्षति का कोई साक्ष्य नहीं है, निम्नलिखित मानदंड दर्शाते हैं कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है:

- क. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में जांच की अवधि में स्वतंत्र और सापेक्ष रूप में वृद्धि हुई है।
- ख. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कीमत में कटौती सकारात्मक और बहुत अधिक है।
- ग. घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा है। घरेलू उद्योग कीमतों में उस सीमा तक वृद्धि करने में सक्षम नहीं हो पाया है जिस सीमा तक यह कर सकता था।
- घ. घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही कीमत पर इस दबाव के फलस्वरूप लगातार प्रतिकूल लाभ और निवेश पर लाभ का स्तर नीचे रहा है। घरेलू उद्योग इस उत्पाद से संबंधित प्रचालनों से उस सीमा तक नकद लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा है जिस सीमा तक यह विगत में प्राप्त कर सका।

ज. प्रकटन पश्चात अनुरोध

87. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात अनुरोध प्राप्त हो गए हैं। प्राधिकारी ने उन्हें दोहराई गई बातों सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है जिनकी पहले ही उचित रूप से जांच कर ली गई है और इन अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में जिन्हें पर्याप्त रूप से हल कर दिया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है:

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा टिप्पणियां

88. प्रपत्र-ख, घ और एनआईपी के निर्धारण के लिए माने गए नियोजित पूंजी संबंधी विवरण घरेलू उद्योग को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। घटाए गए व्यय/जिनकी अनुमति नहीं दी गई है, उनके ब्यौरे भी घरेलू उद्योग को प्रकट नहीं किए गए हैं। एनआईपी आवेदन पत्र में सूचित एनआईपी की तुलना में काफी कम की गई है। इससे क्षति मार्जिन काफी कम हुआ है।
89. की गई कटौतियां और एनआईपी में जिन खर्चों की अनुमति नहीं दी गई है, वे अन्य सार से नहीं घटाए गए हैं। इस प्रकार, एनएसआर और एनआईपी जो भिन्न और अतुलनीय स्तरों पर हैं, इसमें कीमत कटौती भी अधिक दर्शाई गई है।
90. हाल ही में दो जांचें – एक सब्सिडी के लिए और दूसरी पाटन के लिए उसी उत्पाद के संबंध में प्राधिकारी द्वारा की गई हैं। वर्तमान मामले में, प्राधिकारी द्वारा लागू सिद्धांत पूर्व की दो जांचों में लागू सिद्धांत के असंगत प्रतीत होता है। इससे विरोधाभास हुआ है।

अ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा टिप्पणियां

डॉग्स रबर (थाइलैंड) कं. लि.

91. यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने कुछ प्रचालनात्मक मानदंड प्रकट किए हैं, तथापि उन्होंने पाटनरोधी नियमावली के तहत अपेक्षित कई संगत मानदंड प्रकट नहीं किए हैं।
92. यहां तक कि, यद्यपि भारत में संबद्ध सामानों के आयातों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु आयातों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता एक बाधा है क्योंकि वह एक गैर-स्वचालित प्रणाली है। इससे घरेलू उद्योग को संरक्षण मिलता है।
93. थाइलैंड से संबद्ध आयातों में पूर्ण वृद्धि की पाटनरोधी शुल्क और प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने के बाद चीन जन. गण. से आयातों में गिरावट के के संदर्भ में जांच की जानी चाहिए और तदनुसार प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे यह मानें कि कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं है।
94. खपत और उत्पादन के संबंध में वृद्धि बहुत ही कम है और संबद्ध आयातों का भारत में मांग में बहुत ही छोटा हिस्सा है।
95. जांच की अवधि में कीमत कटौती में गिरावट आई। घरेलू उद्योग संबद्ध आयातों के पहुँच मूल्य से न्यूनीकृत हुए बिना अपनी बिक्री लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में सक्षम रहा है।
96. प्रचालनात्मक मानदंडों के कारण कोई क्षति नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और बिक्री की क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।

सियाम ट्रक रेडियल कंपनी लिमिटेड ("एसटीआर") और डिस्टोन कारपोरेशन लिमिटेड ("डीएससी")

97. एसटीआर और डीएससी के उत्तर कोई रद्द करने का माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिया गया कारण यह है कि एसटीआर द्वारा लागत संबंधी आंकड़े दायर नहीं किए गए थे जिससे माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी यह निर्धारित नहीं कर पाए कि एसटीआर और डीएससी के लिए घरेलू बिक्री व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में थी या नहीं।
98. निर्यातकों ने माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी की 24 जनवरी, 2020 की निर्धारित समय-सीमा में अपेक्षित प्रश्नावली के उत्तर दायर किए। तथापि, कुछ लिपिकीय त्रुटियों के कारण, कुछ परिशिष्ट (परिशिष्ट 6, 7 और 8 सहित) अपलोड नहीं किए गए थे और परिणामस्वरूप प्रश्नावली के उत्तर के भाग के रूप में बाद की तारीख में दायर किए।
99. तथापि, एसटीआर ने 23 जुलाई, 2020 को माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास रिकार्ड में अपने लागत संबंधी परिशिष्ट रखे हैं। माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भी एसटीआर द्वारा दायर लागत आंकड़ों का सत्यापन करने के लिए सक्रियता से मांग की। प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों के भाग के रूप में एसटीआर में की गई फाइलिंग में पूरी समय-सीमा दी है – इसमें यह सिद्ध करने के लिए साक्ष्य शामिल हैं कि केवल दायर लागत संबंधी सूचना ही शामिल नहीं थी अपितु माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी विभिन्न ई-मेल पत्रों तथा कई वर्चुअल सत्यापन कॉलों के दौरान माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उसका सत्यापन किया।
100. एसटीआर और डीएससी ने यह अनुरोध किया कि सत्यापित निर्माण लागत तथा बिक्री लागत को रद्द करने का कोई आधार नहीं है। इसके अतिरिक्त, भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 4 और 17 में स्पष्ट रूप से अपेक्षित है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को सहयोगी उत्पादकों तथा निर्यातकों के लिए अलग-अलग मार्जिन की सिफारिश करनी चाहिए। तदनुसार, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे दायर आंकड़ों के आधार पर एसटीआर और डीएससी के पाटन और क्षति मार्जिन का परिकलन करें।
101. उपर्युक्त के पूर्वाग्रह के बिना, यहां तक कि यदि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग करना चाहें तो उसे कम से कम दायर निर्यात कीमत आंकड़ों के आधार पर निर्यातकों के लिए अलग-अलग मार्जिन परिकलित किया जा सकता है क्योंकि ऐसा कोई दावा नहीं है कि निर्यात कीमत या तो अविश्वसनीय है या माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास दायर नहीं की गई थी।
102. एसटीआर और डीएससी का अनुरोध है कि लिखित अनुरोधों और प्रत्युत्तर अनुरोधों के पूर्व में किए गए क्षति संबंधी उनके तर्कों को घरेलू उद्योग के निष्पादन और आयात व्यवहार के बीच सह-संबंध के अभाव के मुद्दे के संबंध में हल नहीं किया गया है।

ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाइलैंड) कं. लिमिटेड, थाई ब्रिजस्टोन कं. लिमिटेड, ब्रिजस्टोन एशिया पेसिफिक पीटीई लिमिटेड, ब्रिजस्टोन सेल्स (थाइलैंड) कं. लिमिटेड और ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("ब्रिजस्टोन ग्रुप")

103. उत्तरदाताओं का अनुरोध है कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग दिया था और प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली के अनुसार सभी आंकड़े तथा अन्य अपेक्षित सूचना प्रदान की थी। सभी अनुरोध रिकार्ड में होने के बावजूद, प्राधिकारी ने उत्तरदाता के अधिकारों का पूर्ण तरह से उल्लंघन करते हुए नोट किया है कि उत्तरदाता ने पूर्णतः कमी वाला स्तर प्रस्तुत किया है। इस निर्णय का उत्तरदाता के हितों के प्रति पूर्वाग्रही प्रभाव है और इसीलिए उत्तरदाता इस व्यवहार का सख्त विरोध दर्ज करता है।
104. यदि प्राधिकारी ने जांच के दौरान यह पाया कि उत्तरदाता द्वारा दी गई सूचना अपर्याप्त है, तो फिर पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.1 के अनुसरण में प्राधिकारी को यह बात उत्तरदाता की जानकारी में लानी चाहिए थी। अनुच्छेद 6.2 में यह प्रावधान है कि "पूरी पाटनरोधी जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके हितों की रक्षा के लिए पूर्ण अवसर होगा"। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6 में यह प्रावधान है कि "पैरा 8 में दी गई परिस्थितियों को छोड़कर प्राधिकारी जांच प्रक्रिया के दौरान खुद को इस बात से संतुष्ट करेंगे कि क्या हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना सही है जिन पर उनके जांच परिणाम आधारित हैं।"
105. याचिकाकर्ताओं ने नियम 6(5) और वर्ष 2018 की व्यापार सूचना के विपरीत अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। याचिकाकर्ता एक्सोटिक डेकर प्रा. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेसटेट के निर्णय के अनुसार अपेक्षित एक्सल फॉर्मेट में लेन-देन वार आयात आंकड़े देने में विफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, बिक्री मूल्य, उत्पादन, निर्यात के लिए सीआईएफ कीमत, वार्षिक रिपोर्ट, घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों और एनआईपी की गणना के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने नियम 7(2) के उल्लंघन में अलग-अलग निष्पादन मानदंडों के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है। एच एंड आर जॉनसन (इंडिया) लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेसटेट का निर्णय कुछ सूचना को गोपनीय रूप में माने जाने के संबंध में उल्लिखित है।

एलएलआईटी (थाइलैंड) कं. लिमिटेड

106. एलएलआईटी ने अपने आरंभिक प्रश्नावली के उत्तर में पहले ही उल्लेख किया है कि उसने असंबद्ध व्यापारियों से जांच में भाग लेने के लिए अपना पूरा अनुरोध किया है। तथापि, एक असंबद्ध पक्षकार होने के नाते वे उन पर जोर नहीं डाल पाए। उत्तरदाता को ऐसी किसी बात के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए जो उनके नियंत्रण के बाहर है। अनुच्छेद 6.13 में यह प्रावधान है कि "प्राधिकारी अनुरोध की गई सूचना देने में हितबद्ध पक्षकारों, विशेष रूप से छोटी कंपनियों के सामने आ रही किसी भी कठिनाई को ध्यान में रखेंगे और कोई भी व्यवहार्य सहायता प्रदान करेंगे।" तथापि, असंबद्ध व्यापारी द्वारा सूचना न दिए जाने के कारण प्राधिकारी का उत्तरदाता के आंकड़े रद्द करना पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.13, 6.4 और 6.2 के उल्लंघन में है।
107. "पूर्ण मूल्य श्रृंखला" सिद्धांत के अनुसार, असंबद्ध कंपनियों की सूचना के आधार पर अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण ऊपर उल्लिखितानुसार सीमा प्रशुल्क अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के विपरीत ही नहीं है बल्कि उस आधारभूत सिद्धांत के विपरीत भी है कि पाटन किसी निर्यातक का कीमत संबंधी व्यवहार है।
108. यह स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि किसी भी असंबद्ध कंपनी की सूचना की उपलब्धता तथा अनुपलब्धता उत्तरदाता निर्यातक के लिए अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, कोई भी कंपनी पाटनरोधी जांच में भाग लेने के लिए किसी भी तरह असंबद्ध कंपनियों को मजबूर नहीं कर सकती।
109. यदि जांच के किसी स्तर पर प्राधिकारी यह पाते हैं कि प्रस्तुत की गई सूचना अपूर्ण थी, तो प्राधिकारी को उत्तरदाता को एक निर्धारित समय के भीतर कमी वाली सूचना प्रदान करने का समय से अवसर प्रदान करना होता है। तथापि, वर्तमान मामले में प्राधिकारी ने रिकार्ड में उपलब्ध सूचना का स्वयं सत्यापन किया और उत्तरदाता कंपनी द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर सत्यापन दस्तावेजों की सूची जारी की।

अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

110. प्राधिकारी ने दोहराई गई बातों सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटन पश्चात टिप्पणियों और अनुरोधों की जांच की और इन अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में उनको उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से हल किया है।

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहली बार की गई प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में उठाए गए तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की जांच निम्नलिखित रूप में की गई है:

111. घरेलू उद्योग का क्षति रहित कीमत में वृद्धि करने और क्षति रहित कीमत के निर्धारण में लगाई गई पूंजी और कुछ खर्च पर विचार करने के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि क्षति रहित कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार किया गया है। क्षति रहित कीमत के प्रकटन के संबंध में उठाए गए मुद्दों के बारे में, यह नोट किया जाता है कि सभी विवरणों के साथ प्रपत्र-एल डीजीटीआर की सतत कार्य-पद्धति के अनुसार घरेलू उद्योग को प्रकट किया गया था। प्रपत्र-एल में कच्चे माल, यूटिलिटी से संबंधित सभी आंकड़े, खर्च का विवरण और लगाई गई पूंजी पर अनुमति दी गई लाभ का ब्यौरा निहित है। कार्यशील पूंजी और एनएफए, जिस पर अधिकारी द्वारा विचार किया गया, का ब्यौरा भी प्रकट किया गया था। प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि निवल ब्रिकी प्राप्ति (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) अलग-अलग स्तरों पर हैं।
112. अगोपनीय रूपांतर में सूचना प्रकट करने के मुद्दे के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता संबंधी अनुरोधों और पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अगोपनीय रूपांतर तैयार किया गया है।
113. एसटीआर और डीएससी ने अनुरोध किया है कि एसटीआर में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को रिकार्ड में लागत संबंधी परिशिष्ट प्रस्तुत किए थे, परंतु कुछ लिपिकीय चूकों के कारण कुछ परिशिष्ट (परिशिष्ट 6, 7 और 8 सहित) अपलोड नहीं किए गए थे और परिणामस्वरूप ये बाद की तारीख को प्रश्नावली के उत्तर के भाग के रूप में दायर किए गए थे। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा विस्तारित 24 जनवरी, 2020 की निर्धारित समय-सीमा के भीतर एसटीआर ने सॉफ्ट कॉपी अथवा हार्ड कॉपी में संगत परिशिष्टों में उत्पादन लागत से संबंधित कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की। तथापि, निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के विवरणात्मक भाग में एसटीआर ने उल्लेख किया कि उत्पादन लागत से संबंधित सूचना प्रस्तुत की जा रही है। इसके बाद, जुलाई, 2020 में अर्थात् प्रश्नावली का उत्तर दायर करने की निर्धारित तिथि के 6 माह बाद एसटीआर ने वास्तव में उत्पादन लागत से संबंधित सूचना दायर की परंतु कुछ लिपिकीय चूकों के कारण कुछ परिशिष्ट (परिशिष्ट 6, 7 और 8 सहित) अपलोड नहीं किए गए थे। यह एक विवादरहित तथ्य है कि पाटनरोधी जांचें समयबद्ध होती हैं। प्राधिकारी किसी भी पक्षकार द्वारा देरी से दायर प्रश्नावली के उत्तर स्वीकार नहीं कर सकते। अतः प्राधिकारी ने एसटीआर और डीएससी द्वारा दायर निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर स्वीकार न करने और इन पक्षकारों के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित न करने का निर्णय लिया है। आगे यह नोट किया जाता है कि केवल इस कारण से कि प्राधिकारी ने इस सूचना का सत्यापन करने का निर्णय लिया, अनुमति दी गई समय सीमा के बाद उत्तर प्रस्तुत करने में विलंब के संबंध में यह नहीं माना जा सकता है कि इसे माफ कर दिया गया है। बढ़ाई गई समय सीमा के भीतर उत्पादन की लागत के निर्धारण से संबंधित परिशिष्टों को प्रस्तुत नहीं करने जैसे प्रमुख डाटा अंतराल सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान ही देखा गया और तदनुसार, प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकारों के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं करने के लिए विवश थे।
114. मैसर्स ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाइलैंड) कं. लिमिटेड, मैसर्स थाई ब्रिजस्टोन कं. लिमिटेड और मैसर्स ब्रिजस्टोन एशिया पेसिफिक पीटीई लिमिटेड द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में कि उन्होंने वर्तमान जांच में पूरा सहयोग किया है और प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली के अनुसार सभी आंकड़े तथा अन्य अपेक्षित सूचनाएं दी हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उनके द्वारा किए गए दावे आधारहीन हैं और उनका कोई औचित्य नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाइलैंड) कं. लिमिटेड, मैसर्स थाई ब्रिजस्टोन कं. लिमिटेड और मैसर्स ब्रिजस्टोन एशिया पेसिफिक पीटीई लिमिटेड ("बीएससीएपी") इन कंपनियों द्वारा दायर उत्तर को रद्द करने के लिए प्रकटन विवरण में उल्लिखित मुद्दों के संदर्भ में कोई ठोस कारण देने में विफल रहे हैं। विशेष रूप से वे यह बताने में विफल रहे हैं कि उत्पादकों ने पृथक निर्यातक प्रश्नावलियां क्यों प्रस्तुत नहीं कीं जो अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, उत्पादकों द्वारा परिशिष्ट-4क, 4ख और 4ग में पृथक सूचना क्यों नहीं दी गई है, उत्पादकों द्वारा परिशिष्ट-6, 8, 9 और 11 क्यों नहीं दिए गए हैं और बीएससीएपी ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में खाली प्रपत्र क्यों प्रस्तुत किए हैं। यह भी नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने केवल इस कारण कि ब्रिजस्टोन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत अपूर्ण सूचना का सत्यापन करने का निर्णय लिया, इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राधिकारी

ब्रिजस्टोन द्वारा दायर उत्तर को स्वीकार करने और ऐसे हितबद्ध पक्षकारों के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए बाध्य हैं। इसके मद्देनजर, प्राधिकारी ब्रिजस्टोन ग्रुप द्वारा दायर निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर को रद्द करने की पुष्टि करते हैं।

115. एलएलआईटी द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में कि उसने असंबद्ध व्यापारियों से जांच में भाग लेने के लिए पूरा-पूरा अनुरोध करने का प्रयास किया और असंबद्ध व्यापारियों द्वारा भाग न लेने से एलएलआईटी को असहयोगी पक्षकार नहीं माना जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि असहयोगी व्यापारियों के माध्यम से भारत को निर्यातों की मात्रा बहुत ही अधिक है (एलएलआईटी द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसार 30 प्रतिशत से अधिक) और उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। भारत को इतनी अधिक मात्रा में निर्यात पर निर्यात कीमत से संबंधित सूचना के अभाव में, भारत को विश्वसनीय निर्यात कीमत निर्धारित करना संभव नहीं है। प्राधिकारी की यह सतत् परिपाटी है कि वे इन परिस्थितियों में उत्तर को स्वीकार न करें। अतः प्राधिकारी एलएलआईटी द्वारा दायर उत्तरों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

ट. भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे

116. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है।
117. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध सामानों का प्रयोग कर विनिर्मित उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामस्वरूप इस उत्पाद की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय से, विशेष रूप से यदि पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति का समाधान करने के लिए आवश्यक मात्रा तक प्रतिबंधित किया जाता है, कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लगाने से पाटन की परिपाटियों से प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट रुकेगी और संबद्ध सामानों के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

ठ. निष्कर्ष

118. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने तथा रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

क) संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों में पूर्ण दृष्टि से तथा पूर्व वर्षों की तुलना में जांच की अवधि के दौरान भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में काफी वृद्धि है।

ख) विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देश से भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है।

ग) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

घ) संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

ड. सिफारिशें

119. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच शुरू करने और जांच करने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक है। अतः प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।
120. नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 17(1)(ख) में निहित प्रावधान के अनुसार, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित, शुल्क तालिका के कॉलम 3 में वर्णित सामानों के

सभी आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों के लिए लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

| क्रम सं. | शीर्ष | विवरण* | मूल देश | निर्यातक देश | उत्पादक | राशि | यूनिट | मुद्रा |
|----------|--------------|--|---------------------------|----------------------|--|--------|--------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | 4011 2010 | बसों और लारियों के लिए ट्यूब और/अथवा फलैप के साथ अथवा उसके बिना रबड़ के के न्यू न्यूमेटिक रेडियल टायर्स* | थाइलैंड | थाइलैंड सहित कोई देश | झोंग्स रबर (थाइलैंड) कं., लि. | 337.80 | मी. टन | अमेरिकी डॉलर |
| 2. | -वही- | -वही- | थाइलैंड | थाइलैंड सहित कोई देश | उपर्युक्त क्रम सं. 1 में एक उल्लिखित के अलावा कोई अन्य उत्पादक | 527.08 | मी. टन | अमेरिकी डॉलर |
| 3. | -वही- | -वही- | थाइलैंड सहित कोई अन्य देश | थाइलैंड | कोई | 527.08 | मी. टन | अमेरिकी डॉलर |

* विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग बसों और लॉरियों/ट्रकों में किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में ट्यूब टाइप और ट्यूबलेस दोनों शामिल हैं।

ढ. आगे की प्रक्रिया

121. इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना के कारण केंद्र सरकार के विरुद्ध की जाने वाली कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क उत्पाद और सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

बी.बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2020

FINAL FINDINGS

Case No. OI- 22/2019

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of “New pneumatic radial tyres of rubber for buses and lorries, with or without tubes and/or flaps” originating or exported from Thailand.

F. No. 6/30/2019-DGTR.—A. BACKGROUND

Automotive Tyre Manufacturer’s Association (ATMA) (hereinafter also referred to as the “Applicant”) filed an application on behalf of domestic industry comprising of Apollo Tyres Ltd., J.K. Tyre Industries Ltd., Ceat Ltd. and MRF Ltd (hereinafter also referred to as the “petitioner/applicant companies”), who are members of ATMA, before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) under the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on imports of new pneumatic radial tyres of rubber for buses and lorries, with or without tubes and/or flaps (also referred to as the “subject goods”), originating in or exported from Thailand (also referred to as the “subject country”).

2. Whereas, the Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/30/2019-DGTR dated 2nd December, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to this subject investigation:

- i. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
- ii. The Authority issued a Notification 6/30/2019-DGTR dated 2nd December, 2019 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from subject country.
- iii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the embassy of the subject country in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 37 days from the date of issue of letter by the authority intimating initiation of the investigation or extended time limit.
- iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
- v. The Authority sent exporter’s questionnaire to the following known producers/exporters in Thailand, whose details were made available by the applicant, to elicit relevant information and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a) Continental Tyres Co., Ltd. Thailand
 - b) Deestone Ltd. Thailand
 - c) Goodyear (Thailand) Public Co Ltd
 - d) Hihero Company Limited
 - e) Huayi Group Co. Ltd. Thailand
 - f) Linglong International Tire

- g) Maxxis International
 - h) Michelin Siam Co, Ltd
 - i) Otani Radial Co. Ltd.
 - j) Sentury Tire (Thailand) Co. Ltd.
 - k) Siam Rubber Ltd.
 - l) SR Tyres Co. Ltd.
 - m) Sumitomo Corporation Thailand Ltd.
 - n) Vee Rubber Corp. Ltd.
 - o) Yokohama Tire Sales (Thailand) Co.Ltd.
 - p) Zhongce Rubber Group
- vi. In response to the above notification, following exporters / producers have filed response to the exporters' questionnaire:
- a) M/s. Bridgestone Asia Pacific Pte Ltd. (BSCAP)
 - b) M/s. Bridgestone Tire Manufacturing (Thailand) Co. Limited (BTMT) and M/s. Thai Bridgestone Co. Ltd (Combined)
 - c) M/s. LLIT(Thailand) Co. Ltd.
 - d) M/s. Zhongce Rubber (Thailand) Co. Ltd.
 - e) M/s. Deestone Corporation Limited
 - f) M/s. Michelin Siam Co., Ltd.
 - g) M/s. Siam Truck Radial Company Limited
- vii. Only written submissions have been filed by Maxxis International (Thailand) Co Ltd. M/s. Otani Radial Co Ltd has only acknowledged the receipt of communication sent by the Authority.
- viii. The Authority sent Questionnaires to the following known importers / users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
- 1) A.G. Industries, Haryana
 - 2) A.S. & Company, Delhi
 - 3) Aditya Sales Corporation, Delhi
 - 4) Agk Digital Private Limited, Delhi
 - 5) Akhil Impex Building, Punjab
 - 6) Alliance Traders, Delhi
 - 7) Amitt Enterprises, Punjab
 - 8) Arora Enterprises, Uttar Pradesh
 - 9) Asis Enterprises, Maharashtra
 - 10) Bhagwatee Impex, Delhi
 - 11) Captown Overseas, Delhi
 - 12) Celite Tyre Corporation, Gujarat
 - 13) Chadha Tyre Traders, Delhi
 - 14) Chhabra Sales Corporation, Delhi
 - 15) Dashmesh Trading Co, Maharashtra
 - 16) Deep Enterprises, Uttar Pradesh
 - 17) Delhi Tyre Shoppe, Delhi
 - 18) Eknoor Tyres Private Limited, Maharashtra
 - 19) Electro Link, Kerala
 - 20) Ess Infraproject Private Limited, Maharashtra.

- 21) Fine Traders, Delhi.
- 22) Fish Aquarium Home, Delhi
- 23) Ganpati Overseas, Delhi
- 24) Genetic Sales Corporation, Delhi
- 25) Globus Corporation, Maharashtra
- 26) Gupta Tyre House, Haryana
- 27) H.D. International, Punjab
- 28) H.S. Arora & Co., Delhi
- 29) H.S. International, Delhi
- 30) Harpreet International, Delhi
- 31) Hayer Trading Co, Maharashtra
- 32) Hind Traders, Maharashtra
- 33) Hind Traders, Delhi
- 34) Indian Rubber Manufacturers Research Association, Maharashtra.
- 35) Indo China Impex, Delhi
- 36) Indo Silicon Electronics P. Ltd, Delhi
- 37) International Business Group, Maharashtra
- 38) J.M. Shama Designs, Maharashtra
- 39) Jaipex, Maharashtra
- 40) Jitender Overseas, Delhi
- 41) Juneja Agencies, Punjab
- 42) K.C. Impex, Delhi
- 43) Kabeer Components Pvt Ltd, Delhi
- 44) Kaks And Bills Pvt Ltd, Delhi.
- 45) Kingston Enterprises, Delhi.
- 46) Lokesh Impex, Rajasthan.
- 47) M S International, Delhi.
- 48) Maankesh Trading Company, Delhi.
- 49) Meenakshi Importers, Maharashtra.
- 50) Mohan Enterprises, Delhi.
- 51) Nand Rubber Pvt.Ltd, Haryana.
- 52) National Trading Company, Delhi.
- 53) New Vikas Tyres, Delhi.
- 54) Pahwa Distributors, Uttar Pradesh.
- 55) Paras Auto Parts, Gujarat.
- 56) Pardeep Import Export, Maharashtra.
- 57) Pioneer Trading Corporation, Maharashtra.
- 58) Pricon Engineering Services, Maharashtra.
- 59) Prem Trading Company, Madhya Pradesh.
- 60) Pricon Engineering Services, Delhi.
- 61) R C International, Maharashtra.
- 62) R S Enterprises, Maharashtra.
- 63) Radhey Kishan Enterprises, Delhi.

- 64) Rajpal Roadlines Pvt Ltd., Maharashtra.
- 65) Rameshwar Dass & Co., Haryana.
- 66) Rangi Road Carrier, Maharashtra.
- 67) Renu Raj Trading, Maharashtra.
- 68) Roadlion International, Delhi.
- 69) Royal Traders, Delhi.
- 70) Rynaa Overseas (India), Maharashtra.
- 71) S R Enterprises, Delhi.
- 72) S. S. And Sons, Delhi.
- 73) S.K. International, Delhi.
- 74) Saarwan Enterprises, Delhi.
- 75) Sabharwal Trading Company, Delhi.
- 76) Sachin Prasad Yadav, West Bengal.
- 77) Samar Traders, Delhi.
- 78) Sanjog Impex, Madhya Pradesh.
- 79) Sanmati Portex Pvt Ltd., Delhi.
- 80) Sat Guru Traders, Uttar Pradesh.
- 81) Saveer International, Delhi.
- 82) Shiv Shakti Enterprises, Delhi.
- 83) Shivalik Exim, Punjab.
- 84) Simran India Inc., Delhi.
- 85) Simran Traders, Delhi.
- 86) Som Projects & Associates, Delhi.
- 87) Ixxxvii. Sri & Co, Karnataka.
- 88) Sri Kumaran Traders, Karnataka.
- 89) Sri Tyres, Karnataka.
- 90) Sumant Bachhawat, West Bengal.
- 91) Sun Traders, Delhi.
- 92) Supreme Trading Corporation, Delhi.
- 93) Surodhya Sales, Delhi.
- 94) Trans Tyres (India) Pvt. Ltd., Maharashtra.
- 95) Uniglory International, Delhi.
- 96) Vaan Sales India Private Ltd, Delhi.
- 97) Vikas Retail Private Limited, Delhi.
- 98) Vortex Rubber Industries Pvt. Ltd., Delhi.
- 99) Vrinda Overseas, Delhi.
- 100) Zafco India Pvt. Ltd., Delhi

ix. In response to the above, following importers / users have filed responses and/or made submissions.

- i. Bridgestone India Pvt Ltd.
- ii. Zafco India Pvt Ltd.
- iii. Force Motors Ltd.
- iv. Renault India Pvt. Ltd.
- v. Triumph Motorcycles (India) Pvt. Ltd.

- x. The Authority, upon request, granted extension for filing Exporter Questionnaire Response (EQR) up to 24.01.2020, which was placed in the public domain through DGTR's website.
- xi. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by all interested parties. A list of all interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to email the NCV of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to ongoing global pandemic.
- xii. The Authority has examined the information furnished by the domestic producers in India to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xiii. Further information was sought from the Applicants and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of present investigation.
- xiv. The Period of Investigation for the purpose of the present anti-dumping investigation is from 1st April, 2018 to 30th June, 2019 (15 Months). The injury investigation period has, however, been considered as the period from April 2015 - March 2016, April 2016 - March 2017, April 2017 - March 2018, and the POI. Since the POI is a period of 15 months duration, the same has been "annualised" for comparison with previous years for the purpose of injury assessment.
- xv. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.
- xvi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in these Final Findings.
- xvii. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in the oral hearing held on 21st October, 2020 which was attended by various parties. The oral hearing was held through video conferencing in view of the special circumstances arising out of the COVID- 19 pandemic. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of these views, in order to enable opposing interested parties to file rejoinders thereafter.
- xviii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xix. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and issued the present final findings on the basis of the facts available.
- xx. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 13th November, 2020 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings.
- xxi. '****' in these Final Findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxii. Information in () bracket indicates negative number/range.
- xxiii. The average exchange rate of US\$1 = ₹ 70.73 prevailing during the period of investigation has been adopted by the Authority for the present investigation.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:

"2. The product under consideration for the purpose of present investigation is "New pneumatic radial tyres of rubber for buses and lorries, with or without tubes and/or flaps" classifiable under 4011 20 10.

3. *The Applicant has claimed that the subject goods produced by the domestic producers and the subject goods imported from the subject country are having comparable characteristics in terms of parameters such as physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods and the two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Based on prima facie examination it is noted that the subject goods produced by the petitioner companies in India is treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country."*

C.1 Submissions made by the Domestic Industry

5. The submissions made by the Domestic Industry with regard to scope of product under consideration are as follows:

- i. The product under consideration is "New Pneumatic radial tyres, of rubber of a kind used in buses or lorries, with or without tubes and/or flap of rubber, classifiable under 4011.20".
- ii. A tyre can be of two types, tube type or tubeless (without tube and flap). In tube type product, tyre is used along with one tube and one flap in a vehicle. A tyre, a tube and a flap are sold together as a "tyre set". The term "TTF" is prevalent in the industry, to denote a "tyre set". Tyre, tube and flap jointly render the function of "tyre" in a vehicle. Air is filled in the tube inside the tyres and a flap is used in between wheel and tube to avoid tube burst. Tyre, tube and flap are produced separately by the producers. Sale of tyre, tube and flap are primarily on "TTF" or "tyre set" basis.
- iii. Radial tyre, tube and flap used in buses and lorries / trucks is included in the scope of the product under consideration, irrespective of whether they are in TTF form or individually as tyre, tube and flap. Tubeless radial tyres, where tube and flap are not required, are also within the scope of this investigation. Tyres, Tubes and Flaps are produced separately. However, they are invariably used together in automotive applications.
- iv. The product under consideration is classified in Chapter 40 under customs subheading no 4011.20 and tubes and flaps are classified under 4013.1010/4013.1020 and 4012.9049 respectively. However, customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of investigation.
- v. There is no difference in product produced by the applicant companies and the subject goods exported from the subject country.

C.2 Submissions made by other interested parties

6. Following submission has been made by other interested parties concerning the scope of product under consideration in the subject investigation.

- a) Deestone Corporation Limited & Siam Truck Radial Company Limited first proposed a PCN system. The PCN structure proposed was based on width/type of tyres/inner dimension/tube type/flap, contending that each of these elements impacts selling price and cost.
- b) Bridgestone initially proposed PCN considering (i)Tyre (ii)Tyre + Tube (iii) Tyre + Tube + Flap (iv) Tyre + Flap. Bridgestone contended that PCNs are not based on the difference in technical characteristics (such as performance, physical features, price, cost and usage differences), but determined by the different product combination (i.e. with or without flap and/or tube). Bridgestone, however, submitted that there is no difference in the production costs with respect to the same tyre product under different PCNs.

C.3 Examination by the Authority

7. The product under consideration (PUC) in the present investigation is "New pneumatic radial tyres of rubber for buses and lorries, with or without tubes and/or flaps", classifiable under tariff heading 40112010 of the Customs Tariff Act, 1975". The scope of the product under consideration includes both tube type and tubeless type radial tyres.

8. In tube type tyre, tyre is used along with one tube and one flap in a vehicle. One tyre, one tube and one flap are together sold as a "tyre set" and described as "TTF". The term "TTF" is prevalent in the industry, to denote a "tyre set". Tyre, tube and flap jointly render the function of "tyre" in a vehicle. Sale of tyre, tube and flap are primarily on "TTF" or "tyre set" basis. Tubeless radial tyres, where tube and flap are not required, are also within the scope of this investigation.

9. The scope of the imported product includes only Radial tyres used in buses and lorries / trucks. Tyres are generally used in various kinds of vehicles such as trucks, buses, lorries, light commercial vehicles, passenger car, jeep, tractor, two-wheeler, three-wheeler, animal pulled vehicles, earthmover, industrial tyres, aircrafts etc. However, the product under consideration is the type that is used in buses & lorries / trucks. All other types of tyres are beyond the scope of the product under consideration in the present investigation.

10. Product under consideration is classified under chapter 40 of the Customs Tariff Act, 1975. Radial tyres are classified under customs tariff item 40112010 whereas tubes and flaps are classified under 40131020 and 40129049 respectively. Tubes and/ or flaps imported without New/Unused pneumatic radial tyres are outside the scope of the PUC. The customs classification is indicative only and in no way binding upon the product scope.

11. After considering the information on record, the Authority holds that there is no known difference between the subject goods produced by the Indian domestic industry and that exported from Thailand. Subject goods produced by the applicants and imported from Thailand are comparable in terms of product characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The product under consideration produced by the applicant domestic industry is like article to the subject product under consideration imported from the subject country.

12. As regards the argument that PCN should be made in the present investigation, it is noted that the interested parties who sought use of PCN methodology withdrew their suggestion. Further, none of the parties provided either relevant information or adequate reasoning justifying use of PCN methodology. It is also noted that the subject goods have been subject to antidumping and anti-subsidy investigation in past, wherein the Authority has not used a PCN methodology. The Authority, therefore, has not used any PCN methodology for the purpose of the present investigation.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Submissions made by the Domestic Industry

13. The submissions made by the Domestic Industry during the course of the investigation with regard to scope of Domestic Industry & standing are as follows:

- i. The application has been filed by Automotive Tyre Manufacturer's Association ('ATMA' or Applicant / Applicant Association), with four members companies of ATMA, viz. M/s Apollo Tyres Ltd., M/s Ceat Ltd., M/s J. K. Tyre Industries Ltd. and MRF Ltd participating in the present application by providing all the relevant information/data as they are the producers of the subject goods in India. There are five other producers of the subject goods, other than the Applicants, i.e. M/s. Birla Tyre, M/s. Goodyear India Limited, M/s Bridgestone India Private Limited, M/s. Michelin India Pvt Ltd, and M/s. Continental India Ltd.
- ii. The applicant companies have not imported the product under consideration from the subject country, and are also not related to any importer in India or any exporter from the subject country.
- iii. The applicant companies hold a major proportion of total Indian production of the product under consideration and account for more than 50% of the production of subject goods in India. Accordingly, the applicant companies constitute 'Domestic Industry' and satisfy the requirement of standing in terms of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the AD Rules.

D.2 Submission made by other interested parties

14. None of the interested parties have made any submission with regard to the scope of domestic industry and standing.

D.3 Examination by the Authority

15. Rule 2(b) of the AD Rules provides as follows:

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

16. The application has been filed by Automotive Tyre Manufacturer's Association on behalf of domestic producers, namely, Apollo Tyres Ltd., J.K. Tyre Industries Ltd., MRF Ltd. and Ceat Ltd. The applicant companies have provided relevant information for the present investigation.

17. The information on record shows that the applicant companies have neither imported the product under consideration from the subject country during the POI, nor they are related to any of the importers of the subject goods in India or exporters of the subject goods from Thailand.

18. Production of the applicant companies constitutes more than 50% of Indian production and thus constitutes a major proportion of total Indian production.

19. The Authority thus holds that the petitioner companies command a major proportion in the production of the subject goods in India and for the purpose of this investigation they satisfy the standing requirement in terms of Rule 5(3) and constitute domestic industry in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

E. CONFIDENTIALITY AND MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**E.1 Submissions made by the Domestic Industry**

20. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to confidentiality issues:

- i. The applicant companies have disclosed all the essential information in the non-confidential version of the application in accordance with Rule 7 of AD Rules and as per Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September 2018.
- ii. Confidentiality claims are limited to information publicly unavailable. Indexed information has been provided wherever feasible and revised non-confidential version of injury statement has been provided.
- iii. Exporters themselves have violated confidentiality norms blatantly preventing applicants from providing comments effectively.
- iv. The applicants have provided sufficient information on imports, import price, dumping margin and adverse impact on numerous economic parameters to warrant imposition of antidumping duty. The interested parties failed to provide comments on sufficiency when abundant time was permitted by the Authority before initiation of the investigation.
- v. Imposition of anti-dumping or countervailing duties on Chinese enterprises globally have resulted in these producers investing in countries outside China. There has been significant investment in Thailand owing to availability of subsidised raw materials. This has eventually led to significant export of tyres from Thailand to various countries including India.
- vi. Earlier trade remedies were to address dumped imports originating from China and had no relation to the dumped imports from new source i.e., Thailand. The shifting of tyre into restricted category only adds licensing requirement and it is no ban on tyres. This will not impact the volume and price of imports.
- vii. The applicant inadvertently missed attaching annexures on export price calculation and adjustments made. It seems interested parties themselves gave little significance to such information, otherwise same could have been requested at a much earlier stage. In any case, the petition has information on CIF prices and ex-factory prices. Revised annexures have been provided for Format H.
- viii. There is no inconsistency between the data provided in IVA and Annexure 1.3. The source of the data in both the annexures are DGCI&S published data, however the information provided in Annexure 4.1 is sourced from Thai customs data.
- ix. The Authority has not carried out segregated analysis for replacement market and OEM market for investigations concerning China.

E.2 Submissions made by other interested parties

21. The following submissions have been made by other interested parties:

- i. The applicant companies have not followed the instructions given in the Trade notice 10/2018 issued by the Authority. In contravention to that the applicant companies have kept several key economic parameters as confidential. Without disclosure of such information the respondent will not be able to make meaningful examination of the injury parameters of the applicant companies. The confidentiality claimed by the applicant companies is excessive.
- ii. The applicant has mostly provided the data for the economic parameters of the participating companies in an indexed form claiming that the actual data may provide a competitive advantage to their competitors. However, if the aggregate data of the participating companies is provided on an actual basis, the individual figures of the participating companies would not be discernible. No competitive advantage would accrue to the respondent or any other competitor.
- iii. The information on these parameters such as capacity, production, capacity utilization, domestic sales, market share, etc. have been disclosed by the Authority in the Final Findings issued in the anti-dumping investigation against China PR. Three of the four participating companies are common to the current investigation and the China anti-dumping investigation on TBR. MRF Ltd., which was not part of the earlier anti-dumping investigation, specifically supported that petition. In that case, the data was not treated as confidential but now it is being claimed as confidential.
- iv. The applicant has also claimed absolute and excess confidentiality in respect of net fixed assets, working capital and capital employed. The applicant has not even provided indexed figures in respect of these parameters.
- v. Rule 5(2) of the AD Rules mandates that an application for initiation of an investigation shall be supported by evidence. The Applicant has failed to provide any evidence that there is dumping and that the Domestic Industry is suffering injury. In the absence of such evidence, the present investigation should not have been

initiated. Reliance is placed on WTO Panel in *DS-60 Guatemala - Anti-dumping investigation regarding Portland Cement from Mexico* and Panel in *DS 264 United States - Final Dumping Determination on Softwood Lumber from Canada*.

- vi. Sufficient protection is available to new pneumatic radial tyres by way of trade remedy measures in the past 3 years.
- vii. Restriction on imports of subject goods imposed by the Directorate General of Foreign Trade in June 2020 needs to be kept in mind by the Authority while recommending imposition of anti-dumping duty in the present case.
- viii. Sufficient protection is available to new pneumatic radial tyres by way of trade remedy measures in the past 3 years.
- ix. Domestic industry is sufficiently protected by existing trade remedial measures and especially after DGFT's decision to move 'new pneumatic tyres' from free to restricted list. The exports of product under consideration in the month of July, August and September 2020 have been reduced to zero.
- x. There are multiple inconsistencies in the petition resulting in deprivation of proper rebuttal opportunity to the interested parties. The period of investigation is 15 months, whereas, data given in Format H POI column is not in an annualized form.
- xi. There is failure on the part of the Domestic industry to segregate information relating to replacement market and OEM market despite submission in the petition that imports are happening only in the replacement market.
- xii. Recent restrictions by DGFT will further reduce supplies from Michelin Siam to Michelin India.

E.3 Examination by the Authority

22. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:

"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

23. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential versions of the evidences/submissions submitted by various interested parties to each other by directing the interested parties to circulate the non-confidential versions of the evidences/submissions through e-mail.

24. As regards the argument that for justifying the initiation of the subject investigation sufficient evidence was not provided indicating dumping causing injury, it is noted that the initiation notification itself mentioned about the Authority finding prima facie evidence of dumping of the subject goods causing injury to the domestic industry. The adequacy and accuracy of evidence thus were examined prior to initiation of investigation.

25. As regards the issue that there is sufficient protection available to the domestic industry, the Authority notes that anti-dumping/ anti-subsidy duties have been recommended only when parameters for the same were satisfied. Moreover, the purpose of anti-dumping duty is to only create a level playing field and provide relief to domestic industry from the injurious effect of dumping and not to provide undue protection to the domestic industry.

26. With regard to submission that restriction on imports imposed by Directorate General of Foreign Trade (DGFT) in June 2020 is further going to reduce supplies, Authority notes that the subject goods have been placed under the restricted category and have not been prohibited for imports. In case of restricted category products, importers would require a licence or permission from the DGFT for imports of such products.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

27. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

(i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

(ii) *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*

- a. *Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- b. *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

F.1 Submissions made by the Domestic Industry

28. The following submissions have been made by the Domestic Industry:

- i. Applicants made efforts to get evidence of the price of subject goods in the domestic market of Thailand. However, they were unable to get any information/evidence of price of subject goods in the form of actual transaction prices. Applicants, therefore, have determined the normal value in Thailand based on cost of production in India, duly adjusted with selling, general and administrative expenses.
- ii. Export price from the subject country has been adjusted for the following expenses, which the exporters from the subject country have incurred for exporting to India, i.e. Ocean Freight, Marine Insurance, Commission, Inland Transportation, and Port Expenses.
- iii. Considering the normal value and export price as above, the dumping margin has been determined, details of which can be seen from the application on record. The dumping margin from the subject country is above de-minimis levels and significant.
- iv. The export price considered by the applicant has been disclosed in the revised annexures. The petition however contained information on CIF price and ex-factory export price and the interested parties were aware of the gross adjustments made by the domestic industry and therefore were aware whether the same is reasonable or not.
- v. The interested parties have not shown existence of any information showing the price at which producers of the product under consideration sell the product in domestic market. Before making a statement, the applicants have done necessary scrutiny about the same.
- vi. Filing of response by a company involved in the production, sales, distribution and marketing of the product under consideration in Thailand or to India is crucial and without that it is not possible to establish the value chain. The exporters have not filed the complete information for the full value chain and therefore their responses should be rejected as per the consistent practice of the Authority.

F.2 Submissions made by other interested parties

29. The following submissions have been made by other interested parties:

- i. Various inconsistencies exist with respect to the construction of normal value and export price, which impact the dumping margin projected by the Applicant.
- ii. There is no explanation of the efforts undertaken by the Applicant to find the domestic prices in Thailand for the purposes of calculating the normal value.
- iii. Thailand is a market economy for which normal value cannot be constructed based on the cost of the domestic industry in India. Explanation (c) to Section 9A (1) of Customs Tariff Act, 1975 ("Act") provides only 3 options for determining normal value for a market economy country - domestic selling price in the exporting country, export price from exporting country to an appropriate third country, or cost of production in the country of origin plus reasonable addition for administrative, selling and general costs and profits. The Petitioner's resort to an arbitrary fourth option which is not provided under the Act is illegal and therefore unacceptable.

- iv. Normal value, export price and dumping margin for the exporters should be based on the information provided in the Exporter's Questionnaire Response.
- v. No positive evidence has been adduced by the Applicant regarding the basis on which certain costs were adopted, thus failing the test of evidentiary requirement under the WTO ADA and the Indian law.
- vi. The Authority should adopt PCN wise comparison while determining the dumping margin in the present investigation.
- vii. The Applicant has arbitrarily used figures for the adjustments to the export price which has unfairly lowered the export price determined. The data presented in the Petition with regard to adjustments are bare assertions unsubstantiated by evidence, which could not have been relied upon for initiating the case.
- viii. Petitioners have not explained the efforts undertaken to find the domestic prices in Thailand for calculation of Normal Value and rather have relied on adjusted cost of production in India. Such computation is not permitted by Explanation (c) to Section 9(A) 1 for a market economy.
- ix. Petitioner's failure to provide evidences for adjustments with regard to export price calculation and no information with regard to Ocean freight results in deprivation of opportunity to the respondent to offer proper rebuttal.
- x. Calculation of normal value as per cost of production in India is not permitted under law for a market economy.

F.3 Examination by the Authority

30. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. In response to the questionnaire sent, following producers/exporters filed the questionnaire response:

- a. M/s. Bridgestone Asia Pacific Pte Ltd. (BSCAP)
- b. M/s. Bridgestone Tire Manufacturing (Thailand) Co. Limited (BTMT) and M/s. Thai Bridgestone Co. Ltd (Combined)
- c. M/s. LLIT (Thailand) Co. Ltd.
- d. M/s. Zhongce Rubber (Thailand) Co. Ltd.
- e. M/s. Siam Truck Radial Company Limited
- f. M/s. Deestone Corporation Limited
- g. M/s Michelin Siam Co. Ltd.

31. As regards the argument of the interested parties for PCN wise comparison in the present case, no valid or compelling reason has been put forth by them for the Authority to consider PCN wise analysis in the present case. None of the exporters have provided adequate reasoning justifying requirement of PCN in the present case. Further, while suggesting PCN wise analysis, these parties have not provided their own information on the basis of the PCN suggested by them. It is also noted that the subject goods have been subject to antidumping and anti-subsidy investigation in past and no PCN wise analysis has been conducted by the Authority in those investigations. Thus, it is noted that PCN-wise analysis need not be done in the present investigation. The Authority, therefore, has determined dumping margin and injury margin for the product under consideration as a whole.

F.4 Determination of Normal Value and Export Price for producers and exporters in Thailand

Normal value for M/s. Bridgestone Tire manufacturing (Thailand) Co. Limited (BTMT), M/s. Thai Bridgestone Co. Ltd (TBC), and M/s. Bridgestone Asia Pacific Pte Ltd. (BSCAP)

32. M/s. Bridgestone Tire manufacturing (Thailand) Co. Limited (BTMT) and M/s. Thai Bridgestone Co. Ltd (TBC) have provided information for both the companies in a single exporter's questionnaire. It is noted by the Authority that exporter's questionnaire response filed by them is grossly deficient. Both producers have not submitted separate exporter's questionnaire which is mandatorily required. It is noted from the response that during the POI both companies have sold in domestic market to various unrelated/ related parties. However, no separate information has been provided in Appendix-4A, 4B and 4C. Further, Appendix-6, 7, 8, 9 & 11 have not been provided by the producers. BSCAP has submitted blank formats in the exporter's questionnaire response. Accordingly, Authority holds to reject the responses filed by M/s. Bridgestone Tire manufacturing (Thailand) Co. Limited, M/s. Thai Bridgestone Co. Ltd and M/s. Bridgestone Asia Pacific Pte Ltd. Therefore, the normal value for these companies is determined on the basis of facts available.

Normal value for LLIT (Thailand) Co. Ltd

33. M/s. LLIT (Thailand) Co Ltd ("LLIT") have provided information pertaining to their domestic sales, exports to India and cost of production in the exporter's questionnaire. LLIT has claimed normal value on the basis of sales made

in the domestic market. However, due to reasons given in subsequent paragraphs, normal value for LLIT has not been determined on the basis of the information provided in exporter's questionnaire response and the same has been determined on the basis of facts available.

Normal Value for Zhongce Rubber (Thailand) Co. Ltd

34. M/s. Zhongce Rubber (Thailand) Co. Ltd has provided information pertaining to their domestic sales and cost of production in the exporter's questionnaire. It is noted from the response that during the POI the company has sold *** MT in domestic market to various unrelated parties. In order to determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. The Authority found that profitable sales are more than ***% and thus the Authority has considered all domestic sales for determination of normal value. The company has claimed adjustments on account of warranty, rebate and inland transportation, which has been allowed by the Authority. Accordingly, normal value determined for M/s. Zhongce Rubber (Thailand) Co. Ltd is mentioned in the dumping margin table below.

Normal Value for M/s Siam Truck Radial Company Limited (Producer) and Deestone Corporation Limited (Exporter)

35. M/s. Siam Truck Radial Company Limited has provided information pertaining to their domestic sales and exports to India in the exporter's questionnaire. However, no information related to cost of production has been provided in the relevant Appendices even though it is mentioned in the descriptive part of exporter's questionnaire that relevant information has been submitted. In fact, the producer has only provided Appendix-1, 2, 3C, 4A & 4B in the exporter's questionnaire. Therefore, Authority is unable to carry out the ordinary course of trade test for the producer. Accordingly, the normal value for Siam Truck Radial Company Limited has been determined on the basis of facts available.

Normal Value for Michelin Siam Co. Ltd. (Producer) and Michelin Asia-Pacific Export (SG) Pte Ltd (Exporter)

36. M/s. Michelin Siam Co. Ltd has provided information pertaining to their domestic sales in the exporter's questionnaire. It is noted from the response that during the POI the company has sold subject goods in domestic market to various unrelated parties. However, the cost of production information required to be provided in Appendix-6, 7 & 8 is grossly deficient. Therefore, Authority is unable to carry out the ordinary course of trade test for the producer. Accordingly, the normal value for Michelin Siam Co. Ltd has been determined on the basis of facts available.

Normal value for all non-cooperative producers/exporters from Thailand

37. Normal Value for non-cooperative producers/exporters from Thailand has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.5 Determination of Export Price

Export Price for M/s. Bridgestone Tire manufacturing (Thailand) Co. Limited (BTMT), M/s. Thai Bridgestone Co. Ltd (TBC), and M/s. Bridgestone Asia Pacific Pte Ltd. (BSCAP)

38. As mentioned above, the Authority holds to reject the exporters' questionnaire responses filed by BTMT, TBC and BSCAP. Accordingly, the Authority holds to determine the export price for these companies on the basis of facts available.

Export Price for LLIT (Thailand) Co. Ltd

39. From the response filed by the producer, the Authority notes that more than 30% of exports to India have been made through Dubai based traders namely M/s. AL Dobowi FZE, ITR Middle East FZCO and Jhinu Impex FZE. These traders have not filed their exporters' questionnaire responses in the subject investigation. Therefore, the Authority holds not to accept the response of LLIT because the complete export chain for a significant portion of the exports made to India is not before the Authority. Accordingly, the export price for LLIT has been determined on the basis of facts available.

Export price for Zhongce Rubber (Thailand) Co. Ltd

40. The Authority notes that M/s. Zhongce Rubber (Thailand) Co., Ltd has exported *** MT of the subject goods to unrelated customers in India. The Company has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland freight, port handling charges and credit cost. The Authority has also made adjustment on account of bank charges to determine net export price at ex-factory level. The ex-factory export price so determined is indicated in the dumping margin table given below.

Export Price for M/s Siam Truck Radial Company Limited (Producer) and Deestone Corporation Limited (Exporter)

41. As stated above, the Authority holds not to accept the exporter's questionnaire response filed by the producer. Accordingly, the Authority has determined the export price for these companies on the basis of facts available.

Export Price for Michelin Siam Co. Ltd. (Producer) and Michelin Asia-Pacific Export (SG) Pte Ltd (Exporter)

42. It is noted from the exporters' questionnaire responses that the exporter has sold the subject goods to a related party in India, namely, M/s. Michelin India Pvt. Ltd (MIPL). MIPL has not provided any information relating to resale of subject goods in India. In view of this deficiency and other facts stated above in the normal value section for these companies, the Authority holds not to accept the exporters' questionnaire response filed by these companies. Accordingly, the Authority has determined the export price for these companies on the basis of facts available.

Export price for all non-cooperative producers/exporters from Thailand

43. The export price for other non-cooperative producers / exporters from Thailand has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.6 DUMPING MARGIN

44. Considering the normal value and export price as determined above, the dumping margin is as follows:

| | Normal value (USD/MT) | Export price (USD/MT) | Dumping Margin | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----|-------------|
| | | | Amount (USD/MT) | % | Range |
| Zhongce Rubber (Thailand) Co. Ltd | *** | *** | *** | *** | 10%- 30% |
| Any other producer/exporter | *** | *** | *** | *** | 20%- 40% |

45. It is seen that the dumping margins are significant and more than the de-minimis limits prescribed under the AD Rules in respect of exports made from the subject country.

G. Determination of Injury and Causal Link**G.1 Submissions made by the Domestic Industry**

46. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury and causal link:

- The demand/apparent consumption of the subject goods increased over the injury period.
- The volume of imports from subject country has increased significantly both in absolute and relative terms.
- Subject imports are undercutting the selling price of the domestic industry and price undercutting is significantly positive.
- Comparison of cost of production and selling price shows that even though the selling price has increased, the increase is less than the increase in cost of production. The imports are causing price suppression.
- Considering the increasing demand, the capacity of the domestic industry has increased over the injury period. Accordingly, production and domestic sales increased. However, production and sales of the domestic industry is lower than what it could have been in the absence of dumped imports, which have increased significantly.
- Profits of the domestic industry have declined significantly. Cash profit, PBIT and ROCE also followed the same trend and declined significantly over the period of injury.
- Market share of the domestic industry should have increased looking at ADD and CVD imposed on imports from China, but to the contrary it has declined.
- The level of inventories with the domestic industry has decreased over the injury period, but remains significant.
- Employment and wages have shown improvement in the injury period. Petitioners produce other goods as well; and, therefore, employment and wages are not solely dependent on the subject goods' performance.

- x. As the information would show, whereas the cost of production increased, the import prices were much lower than the domestic prices and therefore, prevented the domestic industry from increasing their prices in line with the increase in the cost.
- xi. The dumping margin is not only more than de-minimis but also substantial. The impact of dumping on the Domestic Industry is adverse.
- xii. Growth of the Domestic Industry in terms of the majority of parameters such as, profits, return on investment, cash profits, etc. is negative.
- xiii. China has made a huge investment for Truck and Bus radial tyres in Thailand.
- xiv. One of the biggest tyre producer in China, Shandong Linglong Tire Co. has made another huge investment in a new radial truck and bus manufacturing plant. This plant in Thailand is Linglong's fourth domestic manufacturing facility, which will produce 2.4 million truck and bus tires a year at full capacity and will further add to the already surplus capacity available in Thailand. The capacity of the company alone is more than the combined capacity in India. This is clearly indicative of the manner in which Chinese companies are investing outside China in order to beat the increasing trade defence cases against them.
- xv. Imports of subject goods from Thailand have intensified sharply within a short span of time, particularly after imposition of ADD and CVD on subject goods from China. This further increase in capacities in Thailand with an aim to target export markets is indicative of intensified imports into India evidencing further threat of material injury to the domestic industry, in case anti-dumping duties are not imposed.
- xvi. Imposition of anti-dumping or anti-subsidy duties on Chinese tyres by a number of countries globally has made Chinese producers invest in countries outside China. Chinese investment in Thailand has been steadily increasing over the past few years. According to data from the Board of Investment of Thailand, Chinese direct investment in Thailand totals 28 billion baht (about \$ 800 million), making it the 6th largest foreign investor in Thailand.
- xvii. Shandong Linglong Tire Co has already made 1st phase of investment in Thailand in 2012, i.e. an investment of USD 700-million (Bt 24.5 billion) in setting up production facilities for radial truck tires, has made 2nd phase of investment in 2016 and setting up production facilities for natural rubber. The company, in its corporate filing disclosed plans to add 800,000 units of annual capacity for radial truck tires, for 2 million units of radial passenger tires and for 400,000 bias-ply tires. Construction is expected to take 18 months. This could be the 3rd phase of investment or can be part of second phase of investment. This has led to significant exports of tyres from Thailand to various countries including India.
- xviii. Export price from Thailand to India is very low as compared to export price from Thailand to other countries. Exports from Thailand have increased in those markets where Chinese product is attracting trade remedy measures.
- xix. In the present investigation, Chinese dumped goods have shifted to new source and thus domestic industry shows improvement on certain parameters. The EC regulation specially considers this as a factor showing injury. Anti-dumping duty on imports of polyester staple fibres originating in Belarus by EC has been referred in this regard.
- xx. The increase in sale of less profitable exports by the domestic industry is also a sign of injury to the domestic industry.
- xxi. The selective comparison of injury information by interested parties is erroneous. Such examination should take into account entire injury period. The WTO panel report in EC – Tube or Pipe Fittings has been referred to in this regard.
- xxii. The present injury period covers the period of investigation considered for the ADD and CVD investigation on imports from China. The domestic industry is yet to recover fully despite some improvement post imposition of anti-dumping and countervailing duties.
- xxiii. The dumped imports were at the peak in 2016-17 and imports declined thereafter with imposition of ADD on China and initiation of CVD investigation on China. Thus the improvement in performance was as a result of ADD measures imposed.
- xxiv. The reduction in normal value may have been as a result of ideal cost consideration by the directorate even for calculating normal value apart from NIP. The normal value can be calculated on the basis of information provided by exporters in response to the questionnaire.

- xxv. The Indian industry has sufficient capacity to cater to the demand in India. Dumping cannot be justified on account of demand supply gap. CESTAT decision in DSM Idemitsu Limited versus Designated Authority may be referred in this regard.
- xxvi. Domestic industry is still in the process to recover from past ill effects of dumped imports from China and thus the comparison with the situation when imports from Thailand to India was very low, will not give correct picture.
- xxvii. The reference to CESTAT decision in “Bridgestone tyre manufacturing (Thailand) vs. Designated Authority” is erroneous owing to the distinguishing factors in the present case.
- xxviii. It is wrong on the part of the interested party to assume dumping to be the sole cause of injury to the domestic industry. The CEAT’s annual report also emphasises upon recovery stage of the industry from previous ill effects of dumping and subsidised imports. Further, reliance on annual reports are misplaced because of annual reports’ focus on a specific period rather than injury period and annual reports’ concern about overall operations etc.
- xxix. Existence of other factors causing injury does not necessarily break the causal link between dumping from subject country and injury to the domestic industry. The WTO panel report in Thailand - Anti-Dumping Duties on Angles, Shapes and Sections of Iron or Non-Alloy Steel and H-Beams from Poland is relied upon in this regard.

G.2 Submission made by other interested parties

47. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:

- i. Imports from Thailand have increased only after 2017-18. In September 2017, anti-dumping duties were imposed against the importation of the subject goods from China PR. Then, 2018 witnessed an anti-subsidy investigation against the same goods from China PR. Accordingly, the imports of the subject goods from China PR dried up and some portion of that went to Thailand.
- ii. From a perusal of data regarding imports of subject goods in relation to Indian demand, Indian production and Domestic Sales it is clear that the share of the Indian industry was not affected at all.
- iii. The increase in imports from Thailand was a response to the suppression of imports from China PR. Imports from Thailand have never been in competition with the domestic production which has also gained the market lost by Chinese imports.
- iv. The participating Indian companies were able to raise their selling price significantly after the imposition of anti-dumping duty against China PR. The imposition of anti-dumping duty on China PR released the price suppression/depression faced by the participating Indian companies.
- v. Price underselling is not a ‘factor’ to assess injury but rather a tool of measuring the extent of injury, once the same has been established. The AD Rules specifically exclude any mention of price underselling.
- vi. There appears to be no injury to the participating companies in the POI. In fact, after imposition of anti-dumping duties against the imports from China PR, it appears that the economic performance of the participating companies has improved in volume terms as well as on price and profitability parameters.
- vii. The sales quantity, capacity and production quantity of the Domestic Industry has drastically improved during the POI. The most significant growth is seen in the sales of the participating companies, both in domestic and export markets.
- viii. Domestic industry has earned huge profits during POI, making three times more than its PBIT per unit in the previous year. Similarly, cash profits for domestic sales have increased substantially. After a decline in 2017-18, the domestic industry has substantially high cash profits in the POI.
- ix. The injury caused to the Domestic Industry, if any, is attributable to other factors like NBFC crisis, slowdown in automobile industry, increased insurance and fuel prices in India. Despite these factors, the participating companies have made considerable expansion and earned profits as can be seen from CEAT’s annual reports and management analysis report for 2018-19.
- x. The Period of Investigation in the current Petition is 15 months long. However, the data presented by the domestic industry under the POI column in Format H is not in an annualized form. This presents an incorrect situation and poses a difficulty in making a comparison with the previous injury years, which are 12 months long.
- xi. The domestic industry has miscalculated the price undercutting, by considering the incorrect Basic Customs Duty.

- xii. If the Designated Authority imposes the duty on the import of the subject goods, it may cause users of the subject goods to solely depend upon the domestic industry and this will provide unjustified protection to the domestic industry.
- xiii. The domestic industry has failed to provide any details pertaining to the calculation of the Non-Injurious Price beyond an unsubstantiated statement that “the landed prices of imports from subject country is below the level of non-injurious price”. The range of NIP has not been provided, despite an express mandate by the DGTR in this regard.
- xiv. There is no causal link between Michelin imports from Thailand and reduction in sales of Domestic Industry as Michelin Brand Tyres are placed at differentiated / premium price point in the market.
- xv. The increase in volume of imports from Thailand was to fill the demand supply gap resulting from reduction of imports from China. This volume from Thailand has remained in the range of 0-10% throughout the injury period.
- xvi. There is no correlation between price undercutting and injury parameters such as cash profits and total profitability. Further, there is no price suppression. Sales, capacity and production quantity of the domestic industry has improved significantly during the period of investigation. There is no material injury.
- xvii. The injury evidence with regard to cash profits, PBIT and ROCE are on account of period prior to the imposition of anti-dumping duties against imports from China.
- xviii. CESTAT in Bridgestone Tyre Manufacturing (Thailand) vs. domestic industry has miscalculated the price undercutting, by considering the incorrect Basic Customs Duty.
- xix. Exports from Michelin are not causing injury since, such exports are negligent in comparison to annual truck tyre market in India. This is further explained from the fact that the exports from Michelin China to Michelin India are increasing each year despite present anti-dumping imposes the duty.
- xx. There is absence of causal link between exports from Thailand and injury to the domestic industry because of premium price, performance and powerful brand & innovation of Michelin tyres in comparison to domestic tyres. These points were brought before the Authority by a letter given with the written submission.
- xxi. The authority should as per Rule 11, determine threat of injury to domestic industry, causal link and effect on prices in the domestic market of like articles. All three are absent in the present investigation. Michelin brand tyres were sold at 17-22% higher price as compared to prices of domestic manufacturers.
- xxii. The performance of the domestic industry improved significantly despite biggest surge in imports during 2017-18 and the period of investigation.
- xxiii. Appellate body’s report in Anti-dumping measures on Certain Hot Rolled Steel Products from Japan shows the Authority’s obligation to examine all known factors and injury by other factors not attributed to the dumped imports. Final findings in anti-dumping investigations on imports of Ball Bearings (up to 50 mm bore dia.) from China PR, Poland, Russia and Romania; Non-Woven Fabric, originating in or exported from Malaysia, Indonesia, Thailand, Saudi Arabia and China PR; and Belting Fabric exported from Peoples Republic of China has also been referred in this regard. In these findings, the Authority concluded that domestic industry did not suffer material injury on account of the dumped imports.

G.3 Examination by the Authority

48. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties and has examined the various parameters in accordance with the Rules after duly considering the submissions made by the interested parties.

49. Annexure-II of the Anti-dumping Rules provides for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such articles. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

50. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure-II of the Anti-dumping Rules states as follows:

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry,

including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment wages growth, ability to raise capital investments.”

51. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered.

G.4 Volume Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

52. With regard to the volume of dumped imports, the Designated Authority has examined whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure II (ii) of the Anti-dumping rules provides as under:

“While examining the volume of dumped imports, the said Authority shall consider whether there has been significant increase in the dumped imports either in absolute terms or relative in production or consumption in India”

a) Assessment of Demand/Apparent Consumption

53. Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below. The Authority notes that the demand of the product under consideration has increased over the period.

| Particulars | UOM | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | POI | |
|------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|------------|
| | | | | | Actual | Annualised |
| Subject Country | MT | 3,514 | 2,720 | 9,623 | 27,697 | 22,158 |
| Other Countries | MT | 75,790 | 91,292 | 50,152 | 20,798 | 16,638 |
| DI domestic Sales | MT | 348,576 | 356,975 | 404,935 | 603,824 | 483,059 |
| Other Indian Producers | MT | 54,081 | 43,631 | 44,143 | 21,240 | 16,992 |
| Total Demand | MT | 481,961 | 494,619 | 508,854 | 673,559 | 538,847 |

b) Imports in absolute as well as relative term

54. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports from the subject country, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

| Particulars | UOM | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | POI | |
|--|-----|---------|---------|---------|--------|------------|
| | | | | | Actual | Annualized |
| Import Volume | | | | | | |
| Subject Country | MT | 3,514 | 2,720 | 9,623 | 27,697 | 22,158 |
| Other Countries | MT | 75,790 | 91,292 | 50,152 | 20,798 | 16,638 |
| China PR | MT | 69,805 | 85,902 | 42,501 | 14,839 | 11,871 |
| Others | MT | 5,984 | 5,390 | 7,652 | 5,959 | 4,767 |
| Total | MT | 79,304 | 94,013 | 59,776 | 48,495 | 38,796 |
| Subject Country Imports in relation to | | | | | | |
| Indian Production | % | 0.79% | 0.60% | 1.88% | 3.67% | 3.67% |
| Consumption | % | 0.73% | 0.55% | 1.89% | 4.11% | 4.11% |
| Total Imports | % | 4.43% | 2.89% | 16.10% | 57.11% | 57.11% |

55. It is seen from above table that:

- Imports from the subject country have increased significantly during POI (A) in absolute terms as compared to the previous years.
- Imports from other countries have declined. It is noted that imports from China PR have declined significantly after the imposition of anti-dumping and countervailing duty. However, imports from subject country have increased.

c. Imports have increased in relation to production as well as consumption in India.

c) Market Share in demand

56. Market share of subject imports in demand was almost negligible in the base year and the same has increased during the POI(A).

| Market Share in Demand | UOM | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | POI | |
|------------------------|-----|---------|---------|---------|--------|------------|
| | | | | | Actual | Annualized |
| Subject Country | % | 0.7% | 0.5% | 1.9% | 4.1% | 4.1% |
| Other Countries | % | 15.7% | 18.5% | 9.9% | 3.1% | 3.1% |
| DI Domestic Sales | % | 72.3% | 72.2% | 79.6% | 89.6% | 89.6% |
| Other Indian Producers | % | 11.2% | 8.8% | 8.7% | 3.2% | 3.2% |
| Total | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

G.5 Price Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

57. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows-

“With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.”

58. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country have been examined with reference to price undercutting, price suppression/depression and price underselling.

a) Price Undercutting

59. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the Domestic Industry has been compared with the landed value of imports from the subject country. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject country works out as follows:

| Particulars | UOM | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | POI |
|-------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|
| Landed price of imports | Rs/Kg | 170 | 147 | 149 | 168 |
| Net Sales Realization | Rs/Kg | *** | *** | *** | *** |
| | Index | 100 | 95 | 97 | 101 |
| Price undercutting | Rs/Kg | *** | *** | *** | *** |
| | Index | 100 | 136 | 142 | 114 |
| Price undercutting | % | *** | *** | *** | *** |
| | Range | 10-30 | 20-40 | 20-40 | 10-30 |

60. It is seen that the landed price of the subject goods was below the selling price of the domestic industry showing price undercutting being caused by the dumped imports from the subject country during the injury investigation period including the POI. The Authority notes that the level of price undercutting is significant to cause adverse price effect on the domestic industry.

b) Price Suppression and Depression

61. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the changes in the costs and prices over the injury period as compared to the landed price of imports have been considered and are as follows:

| Particulars | Unit | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | POI |
|---------------|-------|---------|---------|---------|-----|
| Cost of Sales | Rs/Kg | *** | *** | *** | *** |
| | Index | 100 | 98 | 104 | 109 |
| Selling Price | Rs/Kg | *** | *** | *** | *** |
| | Index | 100 | 96 | 97 | 101 |
| Landed Price | Rs/Kg | 170 | 147 | 149 | 168 |
| | Index | 100 | 86 | 88 | 99 |

62. It is seen that both cost of sales and selling price have increased over the injury period including the POI. However, import prices have declined during the same period. The cost of sales increased by 9 indexed points during the POI as compared to the base year whereas the selling price increased by 1 indexed points during the same period. It is also seen that the landed price of imports has remained below the level of cost and selling price of the domestic industry throughout the injury period. Thus, imports thus have had suppressing effect on the selling price of the domestic industry.

c) Price Underselling

63. The Authority notes that the dumped imports have caused price underselling effect on the domestic industry:

| Particulars | Unit | POI |
|-------------------------|--------|---------|
| Landed price of imports | Rs/Kg | 168 |
| Non-Injurious Price | Rs/Kg | *** |
| Price Underselling | Rs/Kg | *** |
| Price Underselling | % | *** |
| Price Underselling | Range% | 10%-30% |

Observation on volume effect & price effect

64. The Authority notes that there has been a significant increase in dumped imports, both in absolute terms and in relation to production and consumption in India. Imports are undercutting the domestic prices to a significant degree and are also causing price suppression effect for the domestic industry. The landed price of imports has been significantly below the level of cost of sales of the domestic industry during the period of investigation.

G.6 Economic Parameters of the Domestic Industry

65. Annexure II to the Rules provides that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

a) Production, Capacity, Sales and Capacity Utilization

66. Capacity, production, sales and capacity utilization of the Domestic Industry over the injury period is given in the following table: -

| Particulars | Unit | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | POI | |
|----------------------|------|---------|---------|---------|---------|------------|
| | | | | | Actual | Annualized |
| Capacity | MT | 464,654 | 480,431 | 536,322 | 813,066 | 650,453 |
| Production | MT | 388,152 | 408,089 | 468,124 | 733,743 | 586,994 |
| Capacity utilization | % | 83.54 | 84.94 | 87.28 | 90.24 | 90.24 |
| Domestic Sales | MT | 348,576 | 356,975 | 404,935 | 603,824 | 483,059 |

67. It is noted that the domestic industry has added capacity throughout the injury period. Consequently, production, sales and capacity of the domestic industry have increased.

b) Profitability, return on investment and cash profits

68. Profitability, return on investment and cash profits of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

| Particulars | Unit | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | POI | |
|---------------|---------|---------|---------|---------|--------|------------|
| | | | | | Actual | Annualized |
| Profit/(Loss) | Rs Lacs | *** | *** | *** | *** | *** |
| | Index | 100 | 76 | 57 | 83 | 67 |
| Profits | Rs/MT | *** | *** | *** | *** | *** |
| | Index | 100 | 74 | 49 | 48 | 48 |
| PBIT | Rs Lacs | *** | *** | *** | *** | *** |
| | Index | 100 | 79 | 62 | 93 | 74 |

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | Rs/MT | *** | *** | *** | *** | *** |
| | Index | 100 | 77 | 54 | 54 | 54 |
| | Rs Lacs | *** | *** | *** | *** | *** |
| | Index | 100 | 85 | 77 | 116 | 93 |
| Cash Profit | Rs/MT | *** | *** | *** | *** | *** |
| | Index | 100 | 83 | 66 | 67 | 67 |
| ROCE | % | *** | *** | *** | *** | *** |
| | Range | 10%-30% | 0%-20% | 0%-20% | 0%-20% | 0%-20% |

69. It is noted that:

Profits of the domestic industry declined till 2017-18 and thereafter increased during the POI. While the profits have improved in the POI as compared to 2017-18, they are still lower as compared to 2015-16 and 2016-17. ROCE has followed the same trend. PBIT and Profit per MT has however consistently declined.

c) Employment, wages and productivity

70. Employment and productivity of Domestic Industry over the injury period is given in the table below.

| Particulars | Unit | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | POI | POI(A) |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| No. of Employees | Nos | *** | *** | *** | *** | *** |
| | Index | 100 | 104 | 104 | 103 | 103 |
| Wages | Rs Lacs | *** | *** | *** | *** | *** |
| | Index | 100 | 114 | 133 | 215 | 172 |
| Productivity Per Day | MT/Day | 1,078 | 1,134 | 1,300 | 1,631 | 1,631 |

71. It is seen that number of employees increased till 2016-17, then remained same in 2017-18 and declined thereafter in POI. Productivity has increased during the injury investigation period.

d) Inventories

72. Inventory position with the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

| Particulars | Unit | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | POI |
|-------------|-------|---------|---------|---------|-----|
| Average | MT | *** | *** | *** | *** |
| | Index | 100 | 101 | 92 | 184 |

73. It is seen that the inventories increased in 2016-17, then declined in 2017-18 and increased thereafter in POI

e) Growth

| Particulars | Unit | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | POI -A |
|----------------|-------|---------|-------------|-------------|---------|
| Growth | | | | | |
| Production | % | - | *** | *** | *** |
| | Range | | 0%-20% | 10%-30% | 20%-40% |
| Domestic Sales | % | - | *** | *** | *** |
| | Range | | 0%-20% | 10%-30% | 10%-30% |
| PBT - Domestic | % | - | *** | *** | *** |
| | Range | | (20)%-(40)% | (20)%-(40)% | 10%-30% |
| Cash Profit | % | - | *** | *** | *** |
| | Range | | 0%-20% | 0%-(20)% | 20%-40% |
| ROCE | % | - | *** | *** | *** |
| | Range | | 0%-(20) % | 0%-(20) % | 0%-20% |

74. It is noted that the domestic industry has witnessed a growth in volume as well as price parameters during the POI after imposition of anti-dumping and countervailing duty measures against China PR.

f) Ability to raise capital investment

75. The domestic industry has been making capital investments during the injury investigation period.

g) Factors affecting domestic prices

76. The examination of the import prices from the subject country, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the Domestic Industry in the domestic market, etc. shows that the landed value of imported material from the subject country is below the selling price and the cost of production of the Domestic Industry, causing significant price undercutting as well as price suppression in the Indian market. It is also noted that the demand for the subject goods was showing increase during the injury period including the POI and therefore it could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, it can be said that the imports are affecting the domestic prices of the subject goods.

G.7 Magnitude of Injury and Injury Margin

77. Non-Injurious Price for the domestic industry has been determined on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP has been compared with the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining NIP, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. The production in POI has been calculated considering the best capacity utilisation and the same production has been considered for arriving per unit fixed cost. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. Average Net Fixed Assets plus Average Working Capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive the NIP as prescribed in Annexure-III as per the consistent practice. The non-injurious price so determined has been compared with the landed prices of imports from the subject country to determine the injury margin as follows:

| Particulars | NIP | Landed price | Injury margin | | |
|-----------------------------------|--------|--------------|---------------|-----|--------|
| | USD/MT | USD/MT | Amount | % | Range |
| Zhongce Rubber (Thailand) Co. Ltd | *** | *** | *** | *** | 10-30% |
| Any other producer/exporter | *** | *** | *** | *** | 20-40% |

H. CONCLUSION ON INJURY

78. Considering various parameters relating to material injury, the Authority notes that:

- The dumped imports of the subject goods have increased in absolute as well as relative terms.
- The subject goods are undercutting the prices of the domestic industry in the Indian market.
- Production and sales of the domestic industry have increased over the injury period.
- Profits, cash profits and return on capital employed have improved during the POI as compared to 2017-18 but are below the levels achieved in 2015-16 and 2016-17.
- The landed price of imports from Thailand is below the selling price and cost of sales of the domestic industry.

I. OTHER KNOWN FACTORS AND CAUSAL LINK

79. As per the AD Rules, the Authority, *inter alia*, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the Domestic Industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, *inter alia*, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the Domestic Industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

a) Volume and price of imports from third countries

80. Imports from other countries (except China PR) are low in volume and are at prices higher than import price from Thailand. Further, imports from China PR are already attracting anti-dumping and countervailing duty. Thus, any other third country imports are not causing injury to the domestic industry.

b) Contraction in Demand

81. It is noted that the demand for the subject goods has increased consistently over the entire injury period. Thus, the injury to the Domestic Industry was not due to contraction in demand.

c) Development of Technology

82. The Authority notes that the investigation has not shown any material change in technology for production of the product, which could have caused injury to the domestic industry.

d) Performance of other products of the company

83. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the Domestic Industry does not appear to be a possible cause of injury to the Domestic Industry. Further, Authority has only considered information for the PUC in its examination.

e) Trade Restrictive Practices and Competition between the Foreign and Domestic producers

84. The domestic producers compete with the landed price of the subject imports. The price of the domestic industry is influenced substantially by the landed price of subject goods. Moreover, no evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change. The Authority notes that the imports of subject goods have been put under the restricted category from June 2020 onwards.

f) Export performance

85. The Authority has considered only the domestic performance of the domestic industry in its examination

Conclusion on Injury and Causal Link

86. While there is no evidence of injury being caused by other known factors listed under the rules, the following parameters show that the dumped imports are causing injury to the domestic industry :

- a. Imports of the subject goods from the subject country have increased in absolute and relative terms in the period of investigation.
- b. The price undercutting from the subject country during the POI is positive and significant;
- c. Prices of the domestic industry are suppressed. The domestic industry has not been able to increase prices to the extent it could have.
- d. This price suppression being faced by the domestic industry resulted in continued adverse profits and low level of ROI. The domestic industry has not been able to generate cash profits from operations relating to the product, to the extent it could generate in the past.

J. POST-DISCLOSURE SUBMISSIONS

87. Post-disclosure submissions have been received from the interested parties. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties including reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paragraphs of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.

J.1 Comments by the Domestic Industry

88. Format-B, D and capital employed details considered for determination of NIP have not been made available to the domestic industry. The details of expenses deducted/disallowed have also not been disclosed to the domestic industry. The NIP has been substantially reduced as compared to the NIP reported in the application. This has significantly reduced the injury margin.

89. The deductions made and expenses disallowed in NIP have not been deducted from NSR. Thus, NSR and NIP are at two different and incomparable levels. This has overstated price undercutting as well.

90. In the very recent past, two investigations – one for subsidy and other for dumping – have been conducted by the Authority on the same product. The methodology applied by the Authority in the present case appears inconsistent with the methodology applied in the previous two investigations. This has led to contradictions.]

J.2 Comments by other Interested Parties**Zhongce Rubber (Thailand) Co. Ltd.**

91. Though the Petitioners have disclosed certain operational parameters, they have not disclosed many of the relevant parameters as required under the AD Rules.

92. Even though there is no prohibition on import of the subject goods into India, but licensing requirement is a barrier to imports, because the same is a non-automatic system. This further serves to protect the domestic industry.

93. Absolute increase in subject imports from Thailand must be examined in the context of decline in imports from China PR subsequent to imposition of anti-dumping duty and countervailing duty, and accordingly, the Authority is requested to hold that there is no volume effect.

94. The increase in relation to consumption and production is very minimal, and the subject imports still have a very small share in demand in India.

95. Price undercutting declined in the POI. The domestic industry has been able to increase its selling price commensurate to the increase in its cost of sales, without being suppressed by the landed value of the subject imports.

96. There is no injury on account of operational parameters as the capacity, production, and sales of the domestic industry have increased over the injury period.

Siam Truck Radial Company Limited (“STR”) and Deestone Corporation Limited (“DSC”)

97. The reason provided by the Hon'ble Designated Authority for rejecting STR and DSC's response is that the cost data was not filed by STR whereby the Hon'ble Designated Authority was prevented from determining whether or not the domestic sales for STR and DSC were in the ordinary course of trade.

98. The Exporters filed their requisite questionnaire responses in line with the Hon'ble Designated Authority's prescribed deadline of January 24, 2020. However, due to some clerical omissions, certain appendices (including appendices 6, 7 and 8) were not uploaded and consequently filed as part of the questionnaire response filed at a later date.

99. However, STR has placed its cost appendices on record with the Hon'ble Designated Authority on July 23, 2020. The Hon'ble Designated Authority has also actively sought to verify the cost data filed by STR. As part of the comments to the disclosure statement STR has provided the complete timeline of the filings made – this includes evidence to establish that not only was the cost information filed, but also that the Hon'ble Designated Authority verified the same over the course of various email communications as well as multiple virtual verification calls.

100. STR and DSC submit that there is no basis to reject the verified cost to make and sell. Further, Rule 4 and 17 of the Indian Anti-dumping Rules clearly require that the Hon'ble Designated Authority ought to recommend individual margins for cooperating producers and exporters. The Hon'ble Designated Authority is accordingly requested to calculate STR and DSC's dumping and injury margins based on the data filed.

101. Without prejudice to the above, even if the Hon'ble Designated Authority wished to use facts available for the normal value calculation, it could at least have calculated an individual margin for the Exporters based on the export price data filed, since there is no claim that the export price was either unreliable or not filed with the Hon'ble Designated Authority.

102. STR and DSC submit that their arguments on injury, made in prior written submissions and rejoinder submissions, have not been addressed particularly on the issue of lack of correlation between import behaviour and the performance of the Domestic Industry.

Bridgestone Tire Manufacturing (Thailand) Co Limited, Thai Bridgestone Co Limited, Bridgestone Asia Pacific PTE Limited, Bridgestone Sales (Thailand) Co Limited and Bridgestone India Private Limited (“Bridgestone Group”)

103. The Respondents submit that they had fully cooperated in the investigation and provided all the data and other information required as per the questionnaire issued by the Authority. In spite of having all the submissions on record, the Authority, with gross violation of the rights of the respondent has noted that Respondent has submitted grossly deficient response. This decision has the effect of prejudicing the interests of the respondent and therefore, the respondent registers its strong objection to this treatment.

104. If the Authority during investigation found that there was insufficient information given by the Respondent, then pursuant to Article 6.2 of the Agreement on Anti-dumping the Authority should have brought this to the notice of the Respondent. Article 6.2 provides that “Throughout the anti-dumping investigation all interested parties shall have a full opportunity for the defence of their interests.” Article 6 of Agreement on Anti-dumping provides that “Except in circumstances provided for in paragraph 8, the authorities shall during the course of an investigation satisfy themselves as to the accuracy of the information supplied by interested parties upon which their findings are based.”

105. The petitioners have claimed excessive confidentiality in contravention to Rule 6(5) and Trade Notice 10 of 2018. The petitioners have failed to provide transaction wise import data in excel format as required as per the decision of CESTAT in Exotic Décor Pvt Ltd vs Designated Authority. Further, no information is provided with respect to sales value, production, CIF price for exports, Annual Reports, imports made by Domestic industry and computation of NIP. The petitioners have claimed confidentiality on individual performance parameters in violation of Rule 7(2). The CESTAT decision in H&R Johnson (India) Ltd. Vs. Designated Authority is referred with regard to treatment of certain information as confidential.

LLIT (Thailand) Co. Ltd

106. LLIT in its initial Questionnaire response has already stated that it tried its best to request the unrelated traders to participate in the investigation. However, being a non-related party, they could not force them. The Respondent should not be penalized for something which is beyond their control. Article 6.13 provides that “the authorities shall take due account of any difficulties experienced by interested parties, in particular small companies, in supplying information requested, and shall provide any assistance practicable”. However, the Authority rejecting the data of the Respondent due to non-supplying of information by non-related trader is in violation of Article 6.13, 6.4 and 6.2 of the Agreement on Anti-dumping.

107. As per the 'Complete Value Chain' principle, the determination of individual dumping margin on the basis of information of unrelated entities is not only contrary to the legal provisions of the Custom Tariff Act as highlighted above, but also runs contrary to the basic premise that dumping is a pricing behavior of an exporter.

108. It is clearly established that the availability or non-availability of the information of any unrelated entities can have no detrimental effect on the determination of individual dumping margin for a responding exporter. Moreover, any entity can in no manner force unrelated entities to participate in an anti-dumping investigation.

109. If the Authority at any stage of the investigation finds that the information submitted was incomplete, then the Authority has to provide a timely opportunity to the Respondent to provide the deficient information within a stipulated time. However, in the present case the Authority itself verified the information on record and issued list of verification documents based on the submissions made by the Respondent company.

J.3 Examination by the Authority

110. The Authority has examined the post-disclosure comments/submissions made by the interested parties including reiterations and has suitably and adequately addressed the same in the relevant paras of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions made by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.

111. With regard to the domestic industry's request to increase the NIP and consider certain expenses & capital employed in NIP determination, it is noted that NIP has been determined in accordance with Annexure III of the Anti-Dumping Rules. With regard to issues raised in respect of disclosure of NIP, it is noted that Format-L with all the details was disclosed to the Domestic Industry as per the consistent practice of DGTR. The format-L contains all the figures relating to raw materials, utilities, details of expenses and details of return allowed on capital employed. The details of working capital and NFA considered by the Authority were also disclosed. The Authority further notes that the Net Sales Realization (NSR) and Non-Injurious Price (NIP) are at different levels.

112. With regard to the issue of disclosure of information in non-confidential version, it is clarified that the non-confidential version has been prepared keeping in mind the confidentiality requests made by various interested parties and the legal provisions enshrined in the Anti-Dumping Rules.

113. STR and DSC have submitted that STR had placed its cost appendices on record with the Hon'ble Designated Authority but due to some clerical omission, certain appendices (including appendices 6, 7 and 8) were not uploaded and consequently these were filed as part of the questionnaire response on a later date. In this regard, The Authority notes that STR did not submit any information relating to cost of production in the relevant Appendices either in soft copy or hard copy within the extended deadline of 24th January, 2020 prescribed by the Authority. However, in the descriptive part of Exporters Questionnaire response STR mentioned that the information relating to the cost of production is being submitted. Thereafter, in July 2020, i.e. six months after the due date for filing of questionnaire response, STR actually filed the information relating to cost of production and argued that due to some clerical omission, certain appendices (including appendices 6, 7 and 8) were not uploaded. It is an undisputed fact that anti-dumping investigations are time bound. The Authority cannot accept belated questionnaire response filed by any party. Therefore, the Authority has decided not to accept the Exporters Questionnaire response filed by STR and DSC and not to determine an individual dumping margin for these parties. It is further noted that merely because the Authority decided to verify the information, the delay in submission of response beyond permitted time limit cannot be presumed to be condoned. Major data gaps like the non-submission of appendices relevant to determination of cost of production within the extended time frame came to the notice only during the process of verification and accordingly the Authority was constrained not to determine individual dumping margin for such interested parties.

114. With regard to the submissions made by M/s. Bridgestone Tire manufacturing (Thailand) Co. Limited, M/s. Thai Bridgestone Co. Ltd and M/s. Bridgestone Asia Pacific Pte Ltd that they have fully cooperated in the present investigation and provided all the data and other information required as per the questionnaire issued by the Authority, the Authority notes that the claims made by them are baseless and devoid of any merit. The Authority notes that M/s. Bridgestone Tire manufacturing (Thailand) Co. Limited, M/s. Thai Bridgestone Co. Ltd and M/s. Bridgestone Asia Pacific Pte Ltd ("BSCAP") have failed to provide any cogent reasons w.r.t the issues highlighted in the disclosure statement for rejecting the response filed by these companies. In particular, they have failed to address as to why the producers have not submitted separate exporters questionnaires, which is mandatorily required to be submitted, why no separate information has been provided in Appendix-4A, 4B and 4C by the producers, why appendices-6,8, 9 & 11 have not been provided by the producers and why BSCAP has submitted blank formats in the exporter's questionnaire response. It is further noted that merely because the Authority decided to verify the incomplete information submitted by Bridgestone Group, it does not mean that the Authority is obliged to accept the response filed by Bridgestone Group and determine an individual dumping margin for such interested parties. In view thereof, the Authority confirms to reject the Exporters Questionnaire response filed by the Bridgestone Group.

115. With regard to the submission made by LLIT that it tried its best to request the unrelated traders to participate in the investigation and non-participation by unrelated traders should not result in LLIT being treated as a non-cooperative party, Authority notes that quantity of exports to India through non-cooperating traders are very significant (more than 30% as submitted by LLIT) and cannot be ignored. In the absence of information relating to export price such significant quantity of exports to India, it is not possible to determine the reliable export price to India. It is the consistent practice of the Authority to not accept the response in these circumstances. Therefore, Authority is unable to accept the response filed by LLIT.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

116. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

117. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

L. CONCLUSIONS

118. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

- a) There is substantial increase in imports of subject goods from subject country in absolute terms as well as in relation to production & consumption in India during the POI as compared to the previous years.
- b) The product under consideration has been exported to India from the subject country below its normal value.
- c) The Domestic Industry has suffered material injury.
- d) Material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject country.

M. Recommendations

119. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the Domestic Industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, the authority is of the view that imposition of Anti-Dumping Duty is required to offset dumping and injury. Therefore, Authority recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country.

120. In terms of provision contained in Rule 4(d) & Rule 17(1) (b) of the Rules, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in Column 7 of the duty table below is recommended to be imposed for five (5) years from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of goods described at Column 3 of the duty table, originating in or exported from Thailand.

DUTY TABLE

| Sl. No | Heading | Description * | Country of origin | Country of export | Producer | Amount | Unit | Currency |
|--------|-----------|---|---------------------------------|--------------------------------|---|--------|------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | 4011 2010 | New Pneumatic radial tyres, of rubber of a kind used in buses or lorries, with or without tubes and/or flap of rubber * | Thailand | Any Country including Thailand | Zhongce Rubber (Thailand) Co., Ltd. | 337.80 | MT | US\$ |
| 2. | -do- | -do- | Thailand | Any Country including Thailand | Any producer other than the one mentioned in Serial No. 1 above | 527.08 | MT | US\$ |
| 3. | -do- | -do- | Any Country other than Thailand | Thailand | Any | 527.08 | MT | US\$ |

*The product under consideration is used in buses and lorries/trucks". The scope of the product under consideration includes both tube type and tubeless.

N. FURTHER PROCEDURE

121. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this Final Findings Notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority